NOW NOIDA अपडेट

वॉल्यूम 1 | अंक 9 | September 2024

Title-Code: UPHIN51287

कब तक शहर-शहर होंगी 'निर्भया' दरिंदगी का शिकार?

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावी समीकरण

इतिहास के पन्नों में "बारह बस्तियाँ"

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW

दुनिया देखेगी यूपी का जलवा

Baby Bed Protector

Perfect Baby Bed Sheet Waterproof
for Ultimate Comfort

STARTING FROM ₹125

BUY NOW

sales@madebyindia.com

07011412854

www.madebyindia.com

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

संपादक मंडल

संपादक : संदीप ओझा

सहयोगी संपादक : निर्मल गौड़

नोएडा ब्यूरो चीफ : यूनुस आलम

वरिष्ठ संवाददाता : ओम प्रकाश सिंह, मुस्कान ओझा

संवाददाता : साजिद अली

कला और सयंजोन : अनिरुद्ध शी, गुलशन कुमार

कानूनी सलाहकार मौ. शाहिद, एडवोकेट

प्रबंध निदेशक : संदीप ओझा

निदेशक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 99 इकोटेक 3 उद्योग केंद्र 2 ग्रेटर नोएडा 201306

मुद्रक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD प्लॉट नंबर-99, इकोटेक थर्ड, उद्योग केंद्र-2 ग्रेटर नोएडा-201306
दूरभाष- +91 120-4553364
infonownoida@gmail.com

एमबीआई डिजिटल प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सन्दीप कुमार ओझा द्वारा प्लाट नंबर-99, इकोटेक-थर्ड, उद्योग केंद्र-दो, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) से प्रकाशित व चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिग वर्क प्रा. लि. नोएडा, सी-40, सेक्टर-8 नोएडा से मुद्रिता संपादक सन्दीप कुमार ओझा
(TITLE-CODE: UPHIN51287)

कंटेंट्स

वॉल्यूम 1 | अंक- 9 September 2024 मूल्य: ₹ 50

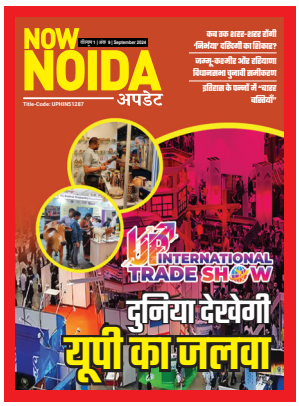

कवर स्टोरी

दुनिया देखेगी यूपी का जलवा

पृष्ठ - 24

कांग्रेस के नहले पर BJP का दहला, OPS, NPS नहीं, क्या UPS से होगा 'सियासी खेला' !	12
हेल्थ बुलेटिन में पढ़िए मंकीपॉक्स से कैसे करें बचाव ?	14
कब तक शहर-शहर होंगी 'निर्भया' दरिंदगी का शिकार?	16
मूंछों वाले 'गब्बर' ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, कैमरे पर बताई अपने दिल की बात	18
जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावी समीकरण	20
इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का बनेगा भव्य पवेलियन	30
लगातार छठवीं बार बसपा की अध्यक्ष बनीं मायावती	32
इतिहास के पन्नों में "बारह बस्तियाँ"	34
बांग्लादेश के युध्द में आंखों के सामने साथियों को शहीद होते देखा, फिर यादें हुई ताजा	38
नोएडा-ग्रेटर नोएडा को लगेंगे चार चांद, जेवर एयरपोर्ट की तैयारी में झोंकी जान !	40
ग्रेटर नोएडा में पहला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट	44
अब बिना अकाउंट कर सकेंगे एक साथ 5 लोग UPI Payment !	46
मोबाइल: युवा पीढ़ी के पतन का कारण!	03
नौकरशाही में लेटरल एंट्री क्या है?	04
पत्नी ने छोड़ा तो हुई महिलाओं से नफरत और कर डाले 11 कत्ल, खूंखार सीरियल किलर की कहानी	06
क्या सीएम योगी सपा का 'मिल्कीपुर तिल्सिम' तोड़ पाएंगे? अभी तक सिर्फ 2 बार ही खिला कमल	10

संपादकीय

बीमारु राज्य से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना?

जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है। क्या उत्तर प्रदेश में ये क्षमता है जिसकी पहचान अब से कुछ साल पहले तक पिछले और बीमारू राज्य के तौर पर हो रही हो। सवाल ये भी कि अपराध और माफिया जिस राज्य की पहचान रहे हों, इंवेस्टर जिधर देखना भी ना पसंद कर रहे हों, वो राज्य आज देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख सकता है? अगर कुछ साल पहले की बात करते तो शायद इसका जवाब ना ही होता, लेकिन मोदी, योगी की डबल इंजन के शासन में राज्य के इस सपने को हकीकत में तब्दील करने में जुटी हैं। इसके लिए पिछले कुछ सालों में कई ऐसे पहल किये जा रहे हैं, जिसने एक उम्मीद जगाई है। इसमें पिछले साल लखनऊ में हुए यूपी ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ, समिट में तीन दिन में कुल 33 लाख, 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए। यहां पर कुल 19 हजार 58 एमओयू साइन हुए। इसी साल ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कहानी को भी दर्शाया गया और बताया गया कि कैसे यूपी की छवि बीमारु राज्य से अनलिमिटेड पोटेंशियल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही बीते सालों में आय़ को कैसे दोगुना किया गया, ये भी लोगों के सामने रखा गया।

कानून-व्यवस्था पर सरकार ने बनाई पकड़

सीएम योगी का सबसे ज्यादा फोकस कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने का है, इसके लिए सरकार अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने की भरसक प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि 25 सेक्टोरेल पॉलिसीज के अलावा उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाता है। एफडीआई और फॉरच्यून ग्लोबल 500 पॉलिसी लेकर आने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लगाएगा चार चांद

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेजी पकड़ाने के लिए प्रदेश सरकार दूसरी बार यूपी इंटनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रही है। पहले एडिशन की सफलता के बाद दूसरी बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 25 से 29 सितंबर को होने जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश के विकास को और मजबूती के साथ पेश करना है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत और यूपी को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा।

संदीप ओझा
संपादक

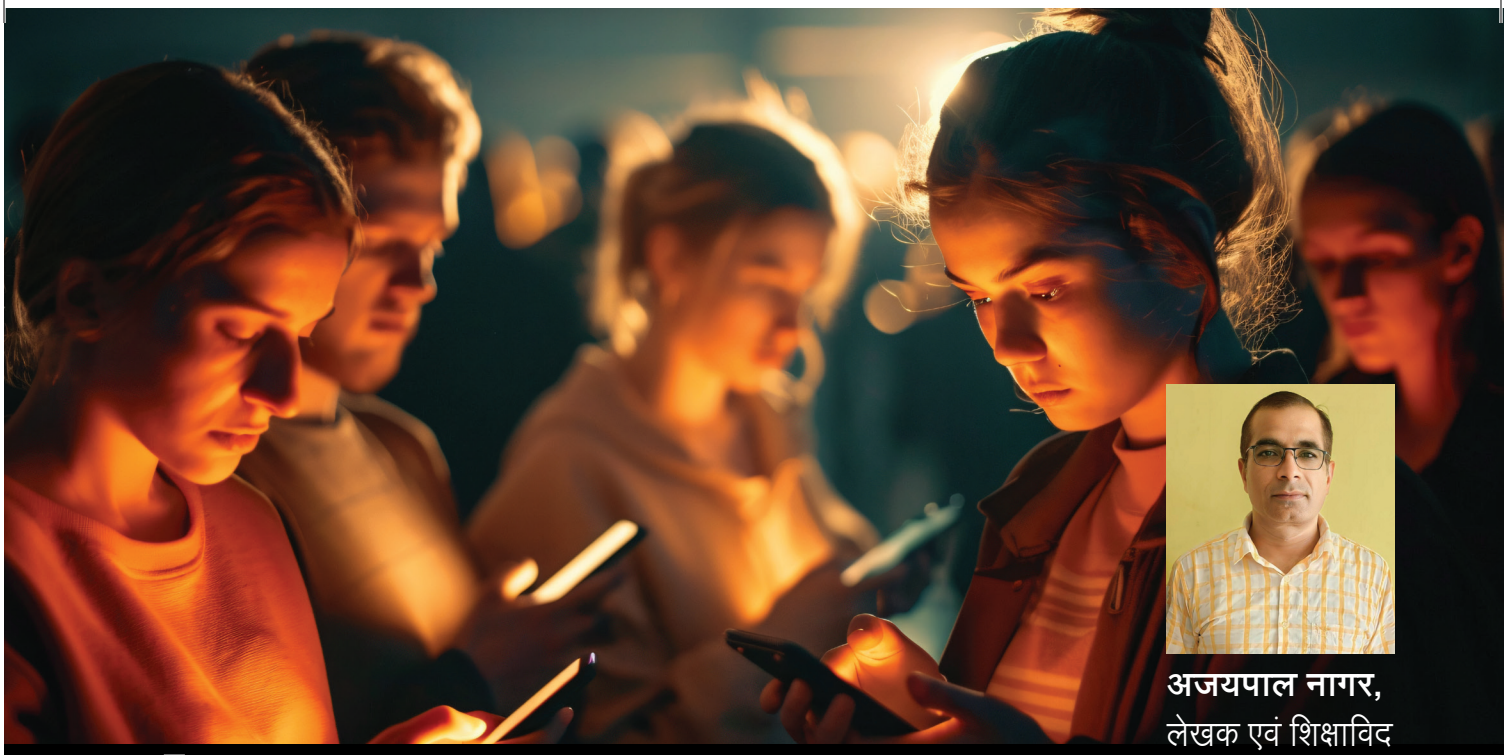

अजयपाल नागर,
लेखक एवं शिक्षाविद

मोबाइल: युवा पीढ़ी के पतन का कारण!

आज का युग विज्ञान का युग है इस युग में विज्ञान ने अनेकों आविष्कार कर मानव जीवन को आराम दायक एवं मनोरंजक बना दिया है।

विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व तरक्की की है उसका कोई जबाब नहीं है। एक वह समय था जब पत्र के माध्यम से समाचार पहुंचाने में महीनों लग जाते थे और एक आज का समय है जब एक क्लिक पर सूचना दुनिया के किसी भी कोने में ईमेल के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से भेजी जा सकती है।

संचार क्रांति ने दुनिया को सचमुच वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ समझा दिया है। जब पूरी दुनिया एक परिवार की तरह आपस में मिल रही है। जब सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए वीडियो कॉल पर परिजनों से रूबरू होते हैं तो यह एहसास नहीं होता कि वह अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है।

संचार क्रांति का जो नकारात्मक प्रभाव वर्तमान युवा पीढ़ी एवं बच्चों पर पड रहा है उसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं नवजात बच्चों से लेकर के स्कूल जाने वाले बच्चों तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई संचार क्रांति के इस दुष्चक्र में फंस चुका है। जिससे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जान पड़ रहा है। कोरोना कल में पढ़ाई के नाम पर शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों को मोबाइल की लत इस कदर लगा दी है कि उन्हें न खाने की चिंता है, और ना पानी पीने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, बस हर समय मोबाइल की चिंता है।

माताओं द्वारा छोटे बच्चों के रोने पर उन्हें मोबाइल हाथ में थमा देना, उसके बाद वह बच्चा धीरे-धीरे मोबाइल की लत का शिकार हो जाता है। जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता ही है साथ ही शारीरिक दृष्टि से भी अत्यधिक कमजोर हो जाता है। बच्चा खेल से बचता है वह हमेशा मोबाइल पर ही बैठा रहना पसंद करता है इससे उसकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है।

समाचार पत्रों में मोबाइल के कारण जान जाने तक के समाचार प्रकाशित हुए हैं। कई बच्चे कानों में लीड लगाकर मोबाइल पर गाने सुनते हुए रेलवे ट्रैक पर चलते हुए रेल दुर्घटना का शिकार हुए हैं। कई बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हुए मोटरसाइकिल पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। सरकार द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित होने के बावजूद भी मोबाइल का उपयोग दुर्घटना का कारण बनता है।

विशेषज्ञों की मानें तो छोटे बच्चों का अधिक समय तक मोबाइल के संपर्क में रहना मानसिक बीमारी को आमंत्रण देना है क्योंकि बच्चों की कोशिकाएं अविकसित होती हैं और मोबाइल की रेडियोएक्टिव तरंगों को सहन नहीं कर पाती और मानसिक बीमारी का कारण बनती हैं। यदि इसी गति से यह सब चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त होगा।

आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करने वाले बच्चों की पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, मानसिक स्थिति असामान्य हो गई है, शारीरक विकास रूक गया है, अनिंद्रा, चिडचिडापन जैसी बीमारियों ने उन्हें अपनी पकड में ले लिया है।

यदि समय रहते मोबाइल के उपयोग पर आयु प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इस देश की युवा पीढ़ी को उनके पतन से कोई नहीं रोक सकता।

बिना UPSC परीक्षा पास किए आईएस के जैसे महत्वपूर्ण पर नियुक्ति यानी नौकरशाही में लेटरल एंट्री (Lateral Entry) पर केंद्र सरकार को यूटर्न लेना पड़ा है। लेटरल एंट्री को लेकर देश में जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। इसका नतीजा हुआ कि यूपीएससी में बिना परीक्षा पास किए लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस के पद जैसे संयुक्त सचिव, निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए निकली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। डीओपीटी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री के तहत 45 पदों की भर्ती के लिए निकले विज्ञापन को रद्द करने के लिए कहा है। आखिर क्या है लेटर एंट्री और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ?

लेटरल एंट्री है क्या?

बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां जॉइंट सेक्रेट्री, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेट्री के पदों पर की होते हैं. निजी क्षेत्र में काम करने वाले 15 साल के अनुभवी वालों की भर्ती अफसरशाही में लेटरल एंट्री के जरिए की जाती है। शामिल होने वालों की उम्र 45 साल होनी चाहिए. आवेदन करने वालों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से कम से कम ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने वालों में शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।

गौरतलब है कि लेटरल एंट्री के तहत पहले दौर की भर्ती 2018 में शुरू हुई. तब सरकार को संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए कुल 6,077 आवेदन प्राप्त हुए थे. यूपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 2019 में नौ अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों में नियुक्ति के लिए नौ प्रोफेशनल्स के नामों की सिफारिश की गई थी। 2021 में लेटरल एंट्री के लिए दूसरी बार आवेदन मंगाए गए थे। फिर मई 2023 में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का विज्ञापन यूपीएससी की ओर से जारी किया गया था। जितेंद्र सिंह ने इस साल 9 अगस्त को राज्यसभा में बताया था कि, 'पिछले पांच वर्षों में लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में, 57 प्रोफेशनल्स केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं.'

नौकरशाही में लेटरल एंट्री क्या है?

कांग्रेस सरकार में किस-किसकी हुई लेटरल एंट्री?

साल 1971 में **मनमोहन सिंह** लेटरल एंट्री के जरिए ही विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सरकार में शामिल हुए थे. वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बने.

रघुराम राजन ने भी लेटरल एंट्री के जरिए ही मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया. बाद में 2013 से 2016 तक वह RBI के गवर्नर रहे.

बिमल जालन ने भी लेटरल एंट्री के जरिए कांग्रेस सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम किया. फिर वह RBI के गवर्नर बने.

सैम पित्रौदा, कौशिक बसु, वी कृष्णमूर्ति, अरविंद विरमानी भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में शामिल हो चुके हैं.

किन देशों में है लेटरल सिस्टम?

भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं, जो लेटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्तियों को सपोर्ट करते हैं. सिविल सर्विस मैनेजमेंट के लिए मशहूर देशों में डायरेक्ट और लेटरल एंट्री सिस्टम है, जिनमें ***ऑस्ट्रेलिया, यूएसए*** और ***यूके*** जैसे देश शामिल हैं. इनके अलावा ***फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया*** और ***स्पेन*** जैसे देशों में भी ये सिस्टम लागू है।

जैसे अमेरिका में कई पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और यहां लेटरल एंट्री सिस्टम का पर्मानेंट पार्ट है. अमेरिका में कई पदों पर इसके जरिए एंट्री होती है और अलग अलग एक्सपर्ट खाली पदों के लिए आवेदन करते हैं. हाल ही में US Department of State ने एक नए लेटरल एंट्री पायलट प्रोग्राम का ऐलान किया था. इस बार मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए ये स्कीम शुरू की गई है, जिसमें मिड लेवल फॉरेन सर्विस के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई. इसके जरिए ग्रेड FP-03 और FP-02 के अधिकारियों की भर्ती की चर्चा है. फेडरल सिविल सर्विस में भी लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति होती है.

इसके अलावा कनाडा में भी लेटरल एंट्री प्रोग्राम है और एजुकेशन भी कुछ कोर्स में सीधे एंट्री दिए जाने का प्रावधान है. अगर यूके की बात करें तो वहां के सिस्टम में भी लेटरल एंट्री के जरिए SCS संभव है, लेकिन अभी इनकी संख्या काफी कम है और ये जरूरी है कि लेटरल एंट्री लेने वाले उम्मीदवार को प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा अनुभव होना चाहिए. वैसे यूके और भारत में सिविल सर्विसेज का सिस्टम लगभग एक जैसा है.

अमेरिका में लेटरल एंट्री सिस्टम काफी कॉमन है और यहां तक वहां

डिफेंस में भी इसके जरिए नियुक्तियां की जाती है. इसमें दूसरे देश के डिफेंस एक्सपर्ट को भी चुना जाता है. वहां भी भारत के UPSC की तरह ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके जरिए लेटरल एंट्री में भी भर्ती की जाती है. ऐसे ही कई देशों में इसे सिस्टम में शामिल किया गया है.

लेटरल एंट्री पर विपक्ष ने घेरा

लेटरल एंट्री पर विपक्ष एक सुर में सरकार के खिलाफ खड़ा है. राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती के सरकार के कदम को राष्ट्र विरोधी कहा. उनका कहना है कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है. राहुल ने कहा कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारा नहीं जा रहा, बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने इसे UPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका करार दिया है.

अश्वनी वैष्णव का तर्क

विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी अवधारणा यूपीए सरकार के समय ही तैयार हुई थी. उन्होंने कहा कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) यूपीए सरकार के दौरान साल 2005 में गठित किया गया था. जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे. आयोग ने खास नॉलेज की जरूरत वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी. अश्वनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां 1970 से कांग्रेस सरकारों के दौरान होती रही हैं. ऐसी पहलों के उदाहरण में उन्होंने मनमोहन सिंह, मोटेक सिंह आहलूवालिया का नाम लिया.लेटरल एंट्री से अब तक कितनी भर्तियां हुई हैं?

पत्नी ने छोड़ा तो हुई महिलाओं से नफरत और कर डाले 11 कत्ल

खूंखार सीरियल किलर की कहानी

पत्नी ने साथ क्या छोड़ा पति ने एक दो नहीं बल्कि 11 कत्ल की वारदातों को अंजाम दे डाला. ये सोचकर यकीन नहीं होता है लेकिन ये बात सच है, ये सच्ची घटना है UP के बरेली जिले की, जिसे झुमकानगरी भी कहा जाता है लेकिन ये कातिल झुमका तो चोरी करता था ही साथ में उन्हें मार भी डालता था. जो आप तस्वीर देख रहे है. ये उसी सीरियल किलर की है जिसने खौफ से महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं जाती थी. जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

ये वही आरोपी है जिसने एक, दो नहीं बल्कि सिलेवार तरीके से कई महिलाओं के कत्ल को अंजाम दिया, इसका नाम तो कुलदीप है लेकिन कारनामे नाम से ठीक विपरीत, एक बार पत्नी छोड़कर मायके क्या गई फिर महिलाओं से ऐसा बदला लिया कि 14 महीनों तक 11 महिलाओं की गांवों में हत्या कर डाली, जिसने ऐसी दहशत पैदा कर दी कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी, जिन 11 महिलाओं का कत्ल हुआ उन सब हत्याओं का पैटर्न बिल्कुल एक सा था. जिसने बरेली में ऐसा खौफ भरा कि महिलाएं घरों से बाहर झांकने में भी कतराती थी. शाम के बाद कोई अपने घर का गेट तक नहीं खोलता था ऐसा 10, 20 नहीं बल्कि 90 से ज्यादा गांवों में इस सीरियल किलर का खौफ था जिसे पुलिस ने अब दबोच लिया है लेकिन इस शातिराना कातिल की कहानी के पीछे कई राज दफ्न है, जिसे इस रिपोर्ट में समझते है

नाम: कुलदीप गंगवार उम्र तकरीबन 35 साल

गुनाह: 11 महिलाओं के कत्ल का आरोप

वजह: पत्नी के छोड़ने पर महिलाओं से नफरत

जी हां ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि कुलदीप गंगवार ने अपने गुनाहों को कबूल किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बाकरगंज समुआ का निवासी है, जो की साइको किलर है, कुलदीप की हरकतों की वजह से पत्नी उसे शादी के कुछ ही सालों बाद छोड़कर चली गई थी. इसके बाद उसने महिलाओं की हत्या करना शुरू कर दिया. उसने सालभर के भीतर 11 महिलाओं की हत्या कर डाली थी. लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक आरोपी ने 6 महिलाओं के कत्ल की वारदातों को कबूला है. हालांकि एसएसपी अनुराग आर्या का कहना है कि हत्याएं और भी की है इस मामले में कातिल से पूछताछ की जाएगी.

दावा है कि दस साल पहले कुलदीप की शादी भानपुर गांव निवासी लौंगश्री से हुई. उसकी हरकतों से परेशान लौंगश्री ने दूसरी शादी कर ली. बताते हैं कि तभी से वो महिलाओं से नफरत करने लगा. उसकी बुआ का घर शाही के सब्जीपुर खाता गांव में है. यहां वो आता जाता था. पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने ही महिलाओं से नफरत की वजह से उनकी सिलसिलेवार तरीके से हत्या की. यहां तक की कत्ल करने के बाद महिलाओं की कोई निशानी को जरूर कातिल चुरा लेता था, गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कई टीमों ने उसे घटनास्थलों पर ले जाकर घटना का रीक्रिएशन किया है.

इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2023 को जब बरेली के आनंदपुर गांव में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. क़ातिल ने करीब 55 साल की प्रेमवती की जान उसी की साड़ी की पल्लू से गला घोंट कर ली थी. जांच तो इस मामले में पुलिस ने शुरू की, लेकिन उसे क़ातिल का कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि शातिराना अंदाज में कातिल ने इस वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद अगले पांच महीनों में रह-रह कर कुछ इसी तरह बरेली के अलग-अलग गांवों में महिलाओं की हत्या होती रही और गिनती 6 तक पहुंच गई गौर करने वाली ये रही की सभी मामलों में क़ातिल ने 50 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया और सभी मामलों में क़त्ल का हथियार महिलाओं की साड़ी का पल्लू या फिर उनका दुपट्टा रहा. बरेली पुलिस जांच करती रही, अफसरों के तबादले होते रहे लेकिन अभी तक कातिल का पता नहीं लग सका जिन महिलाओं का क़त्ल हुआ, उनके घर वाले इंसाफ के लिए भटकते रहे, लेकिन पुलिस थानों में क़त्ल के उन मामलों की फाइल धूल फांकती रही. लेकिन फिर से एक बार पुलिस को सीरियल किलर ने चुनौती दी क्योंकि चंद महीनों के गैप के बाद फिर से बरेली के एक गांव में हत्या वैसे ही हुई जैसे पहले हुई थी इस बार क़ातिल ने 45 साल की एक महिला की जान उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर ले ली.

रिपोर्ट्स की मानें तो

1 जुलाई 2023- शाही इलाके के आनंदपुर गांव में 55 साल की प्रेमवती की हत्या

21 जुलाई 2023 - शाही इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की धनवती की हत्या

1 नवंबर 2023 को शीशगढ़ में 65 साल की महमूद की हत्या- लाश खेत में मिली

9 नवंबर 2023 को खानपुर गांव की 55 साल की ओमवती की हत्या - लाश खेत में मिली

20 नवंबर 2023 को खुरसैनी में 65 साल की दुलारो देवी की हत्या - लाश गांव के बाहर मिली

26 नवंबर 2023 को शीशगढ़ के जगदीशपुर गांव में रहने वाली 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या

2 जुलाई 2024 - शाही थाना के गांव बुझिया जागीर में 45 साल की अनिता की हत्या

इस लिस्ट को गौर से देखें तो बरेली के ग्रामीण जिले के दो थाना इलाकों मीरगंज सर्किल के शाही और शीशगढ़ में ही सारी की सारी वारदातों को अंजाम दिया गया. अब तक आई खबरों की मानें तो इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी भी मामले में महिलाओं के साथ रेप-छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले. क़त्ल के ज्यादातर मामले खेतों में या उसके आस-पास के हैं और सभी के सभी मामलों में महिलाओं के घरवालों ने किसी

दुश्मनी से इनकार किया है. ऐसे में ढेरों सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे, कि आखिर वो आरोपी को गिरफ्तर क्यों नहीं कर पाई, लेकिन अब सब कत्लों का जवाब कुलदीप से मिल गया है. उसने हत्या की वारदातों को कबूल किया है.

बता दें 6 अगस्त को ही पुलिस ने सीरियल किलर का स्केच तैयार करवाया था. डीजीपी के हुक्म पर पुलिस ने सीरियल किलर के स्केच बना कर तलाश शुरू की जिसको लेकर अब सफलता मिली है, लेकिन इस कातिल के नफरत की आग किस कदर भरी हुई थी, वो सब इसकी हरकतों को देख आप भी समझ सकते हैं.

SSP अनुराग आर्या ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी और कहा था कि

हत्याओं के खुलासे के लिए वॉर रूम बनवाया

'ऑपरेशन तलाश' इसका नाम दिया गया

22 टीमों का गठन, 1500 CCTV लगवाए गए

25 किलोमीटर में करीब 600 नए कैमरे लगे

महाराष्ट्र भेजकर सीरियल किलर को लेकर स्टडी

1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डाटा लेकर सर्विलांस मदद

किसानों के रूप में पुलिस को लगाया, बॉडी बॉर्न कैमर

खुफिया कैमरों के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है लेकिन जिन महिलाओं का इस कुलदीप ने कत्ल किया उनके घर में आज भी मातम छाया हुआ है.

MBI
Direct From Factory
PARTNER WITH MADE BY INDIA
Expand & Accelerate Your Business's Growth
No Capital Investment required
Partner with the Market Leader
sales@madebyindia.com
07011412854
www.madebyindia.com

WEB Cadence INDIA
GET YOUR
DYNAMIC WEBSITE WITH CMS PANEL
Our Best Service
4-5 CUSTOM PAGES
WHATSAPP CHAT INTEGRATION
CONTACT FORM FOR LEAD GENERATION
GOOGLE MAP INTEGRATION
MOBILE FRIENDLY
SEO FRIENDLY
+91 7982133887
www.webcadenceindia.com
asha@webcadenceindia.com
**TERMS & CONDITIONS APPLY

क्या सीएम योगी सपा का 'मिल्कीपुर तिल्सिम' तोड़ पाएंगे? अभी तक सिर्फ 2 बार ही खिला कमल

अयोध्या मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर विधानसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. इस बार लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा के अयोध्या हारने से सियासत गर्म है.वहीं, सपा लोकसभा चुनाव की जीत को बरकरार रखे के लिए पूरी तैयारी में है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है. जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है. उपचुनाव लड़ रही बसपा ने तो उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं. अयोध्या के मिल्कीपुर (सुरक्षित) से समाजवादी पार्टी से विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है. इस सीट पर 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे रामगोपाल कोरी पर मायावती ने इस बार दांव लगाया है. वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद ले ली है.

सीएम ने खुद ली मिल्कीपुर की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे में एजेंडे में राम

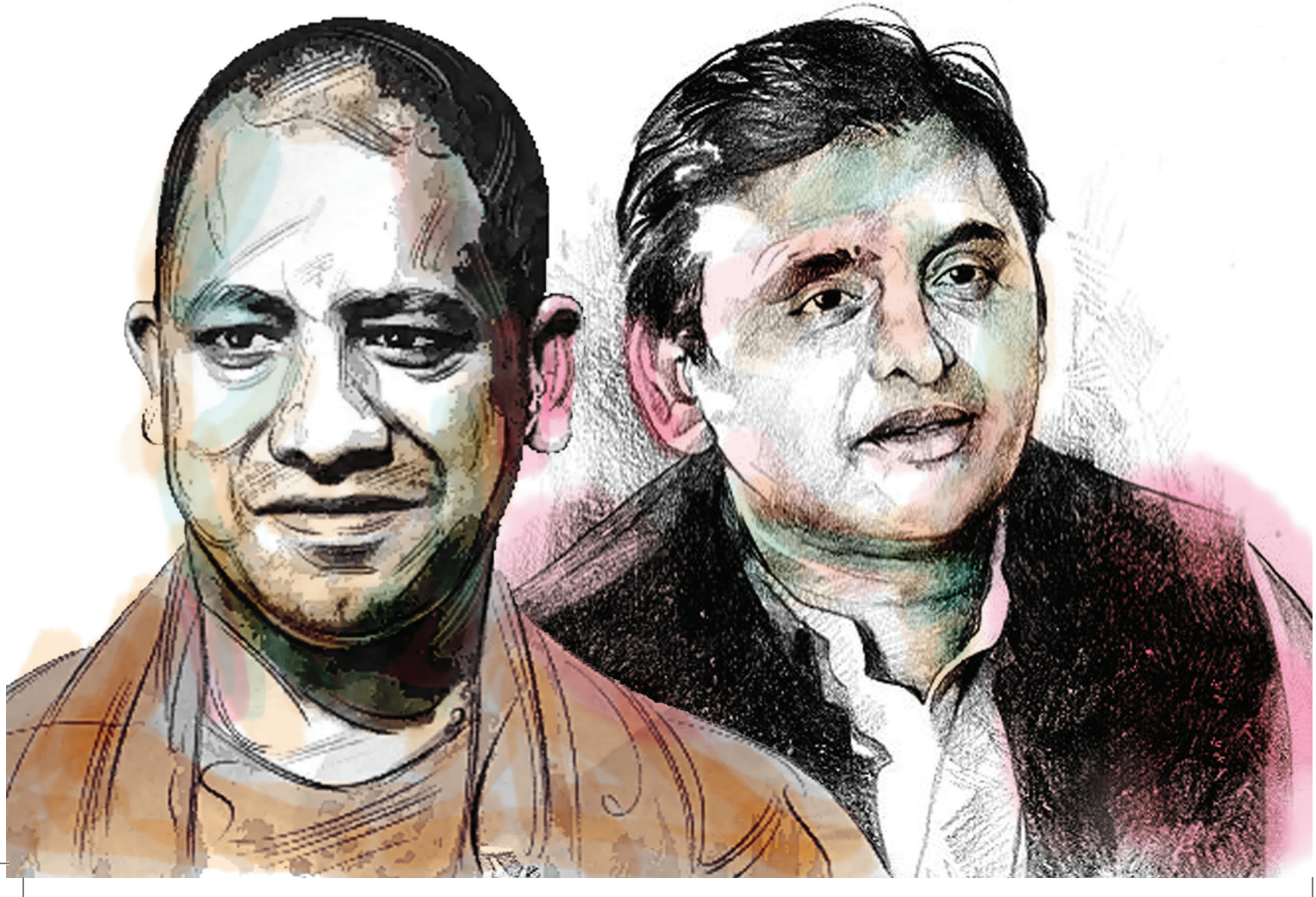

मंदिर प्रमुख रहा. लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रधानमंत्री पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी भाजपाई नेताओं ने श्रेय लिया. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक को रामभक्तों का हत्यारा बताया. भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अभियान चलाया और वाहवाही लूटी थी. लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से भाजपा हार गई. मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए. यही नहीं, अयोध्या के आसपास की भी सीटें भाजपा हार गई. अयोध्या सीट हारने से योगी सरकार को खूब फजीहत हुई. काफी दिनों तक हार की समीक्षा चली. अब इस हार का बदला लेने के लिए उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी खुद ली है. सीएम योगी अयोध्या का दौरा नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ ही अगली रणनीति बना रहे हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी की भी पोल खोलकर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

अयोध्या रेप केस क्या भाजपा को देगा बूस्ट डोज?

माना जा रहा है कि अयोध्या में हार का बदला उपचुनाव में लेने के लिए नाबालिग बच्ची का मुद्दा सीएम योगी ने विधानसभा में जोर शोर उठाया था. अयोध्या रेप केस में सपा नेता मोइद खान का नाम सामने आने के बाद लगातार सपा पर हमलावर हैं. इसके साथ ही मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही हैं. वहीं, पीड़िता और उसके परिजनों को पूरी मदद कर सीएम योगी जनता को खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो अयोध्या रेप कांड उपचुनाव में भाजपा के लिए बूस्टर साबित हो सकता है. क्योंकि भाजपा को सपा की कमजोर कड़ी मिल गई है.

क्या अवधेश सपा के फिर बनेंगे तारनहार?

इन्हीं में से एक है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिसके विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए हैं. अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को ही मिल्कीपुर का प्रभारी बना दिया है. बीजेपी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यही मौका है, जब वो अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी को जिताकर लोकसभा में हुई हार का बदला ले सकें. लिहाजा मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का प्रभारी और कोई नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं.

सापा और भाजपा से कौन-कौन दावेदार

विधायक से सांसद बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को सपा के टिकट का सबसे अधिक दावेदार बताया जा रहा है। अजीत की उम्मीदवारी की घोषणा सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कुछ दिन पहले कर चुके हैं. हालांकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर कोई बयान अभी तक नहीं आया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक

2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने 103,905 वोट पाकर विधायक बने थे. अवधेश प्रसाद को 47.99 फीसदी वोट मिला था. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 90,567

और 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रहे गोरखनाथ के अलावा भी कई दावेदारों के नाम सामने आये हैं. इनमें से पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया और काशीराम रावत दावा ठोक रहे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में क्या थी स्थिति

2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने 103,905 वोट पाकर विधायक बने थे. अवधेश प्रसाद को 47.99 फीसदी वोट मिला था. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 90,567, बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427, कांग्रेस प्रत्याशी नीलम कोरी को 3,166 वोट मिले थे. जबकि 1,960 ने नोटा विकल्प चुना था.

विधानसभा सीट का इतिहास

गौरतलब है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए पहलीबार 1967 में चुनाव हुआ था. इस सीट से सबसे अधिक मित्रसेन यादव विधायक चुने गए हैं. मित्रसेन 4 बार कम्युनिष्ट पार्टी तो एक बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं. जबकि कांग्रेस को इस सीट पर तीन बार सफलता मिली है. जबकि समाजवादी पार्टी के पांच विधायक चुने गए हैं. कम्युनिष्ट पार्टी के 4, भारतीय जनता पार्टी 2, बसपा और भारतीय जनसंघ पार्टी के खाते में 1-1 बार यह सीट गई है.

मतदाता और जातीय समीकरण

बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 340820 वोटर्स थे. जिनमें पुरुष 182430 और महिला मतदाता 158381थीं. जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण, 60 हजार, यादव 55 हजार, पासी 55 हजार, मुस्लिम 30 हजार, ठाकुर 25 हजार, दलित 25 हजार, कोरी 20 हजार, चौरसिया 18 हजार, वैश्य 12 हजार, पाल 7 हजार, मौर्य पांच हजार और अन्य 28 हजार वोटर्स हैं.

कांग्रेस के नहले पर BJP का दहला, OPS, NPS नहीं, क्या UPS से होगा 'सियासी खेला' !

OPS, NPS और UPS, ये तीनों पेंशन स्कीम को लेकर इन दिनों हंगामा खड़ा हो गया है. एक ओर जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने UPS को मंजूरी दे दी है, यानी विपक्ष के सवालों की काट के लिए नहले पर दहला मारा है. दरअसल OPS को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते है, विपक्ष से लेकर सरकारी कर्मचारी इसे दोबारा लागू करने की मांग करते रहे हैं., लेकिन अब जब कुछ ही समय में हरियाणा, जम्मू के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले मोदी सरकार यूनीफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS ले आई है, जिसे सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. हालांकि UPS, OPS और न्यू पेंशन स्कीनम, जिसने नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते है, वो बिल्कुल अलग है. तीनों में क्या अंतर है, ये जानना बेहद जरूरी है.

OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ?

एक ऐसी पेंशन स्कीम जिसके तहत, सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर हर महीने पेंशन देने का प्रावधान है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था. हालांकि, इसकी जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध भी हुआ अब तक के चुनावों में OPS को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है, OPS सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी, 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए हैं. OPS के तहत पेंशन को महंगाई भत्ते यानी DA में होने वाले बदलावों के मुताबिक, समय-समय पर अडजस्ट किया जाता है, जो महंगाई से जुड़ा होता है. OPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता था.

क्या है NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम ?

न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS, जिसको 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च किया था. इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू किया था. अक्सर इसका विरोध देखने को मिलता है. इसके तहत कर्मचारियों से भी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन लिया जाता है. आसान भाषा में समझें तो NPS के तहत मिलने वाला पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दरमियान किए गए कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है, और मार्केट परफोर्मेंस के आधार पर देने का प्रावधान है. इसमें सरकारी कर्मचारी को अपने बेसिक पेमेंट और DA का 10% योगदान देना होता हैं. सरकार इसमें 14 फीसदी का योगदान करती है.

NPS में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं

टियर I

ये एक मैंडेटरी अकाउंट है, जिसमें रिटायरेंट पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं.

टियर II

ये एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है, जिससे किसी भी समय कर्मचारी अपने पेंशन की रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता.

बताया जाता है कि कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त एक्यूमुलेटेड कॉर्पस के तौर पर पेंशन की 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं, बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए किया जा सकता है. इतना ही नहीं अगर आपका अकउंट NPS के तहत आता है, और आप अगर एकमुश्त 60 फीसदी रकम निकालते हैं तो इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 40 फीसदी रकम पर आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा.

क्या है UPS यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम ?

UPS में सरकारी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में जो सैलरी मिलेगी, उस सैलरी के बेसिक पे के तहत 50 प्रतिशत के बराबर की एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी. हालांकि इसका फायदा 25 साल की नौकरी पूरी करने वालों को ही मिलेगा. अगर 10 साल की सरकारी नौकरी करके छोड़ देते हैं, तब भी 10,000 रुपए की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी यानी UPS में पेंशन पाने के लिए आपको 10 साल नौकरी करना अनिवार्य होगा. UPS में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को तुरंत 60 प्रतिशत पेंशन दे दी जाएगी.

एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन पर महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. ये आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फार इंडस्ट्रियल वर्कर्स के मुताबिक होगा. इस पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी के साथ सुपरएनुएशन का पेमेंट भी किया जाएगा. सुपरएनुएशन पर कर्मचारी को ठीकठाक पेमेंट मिले, इसके लिए कर्मचारी के हर 6 महीने की नौकरी पूरी कर लेने के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से को ग्रेच्युटी में जोड़ा जाएगा. इस पेमेंट का कर्मचारी के एश्योर्ड पेंशन पर असर नहीं होगा. UPS के लिए कर्मचारी को अपने बेसिक पे का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा. जबकि सरकार की ओर से बेसिक पे का 18.5 प्रतिशत जमा किया जाएगा. ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. हालांकि UPS में बड़ा सवाल ये है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC को सरकारी नौकरी में उम्र का रिलेक्शन मिलता है. कई राज्यों में सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्र 40 साल तक है, तो उन्हें एश्योर्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. जबकि OPS में ऐसी कोई शर्त नहीं है, अब सरकार ने तो OPS और NPS की तोड़ के लिए UPS को मंजूरी दे दी है. अब आगे आने वाले समय में इसका असर वोटबैंक पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी.

हेल्थ बुलेटिन में पढ़िए मंकीपॉक्स से कैसे करें बचाव ?

Mpox यानी मंकीपॉक्स, जिसके नाम से लगता है इसका बंदर से कोई न कोई जरूर कनेक्शन है अगर आप भी पढ़ते हुआ ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1950 के दशक में दुनियाभर में जब पोलियो की बीमारी फैल गई थी तब साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में लगे थे. इस दौरान साइंटिस्टों को बंदरों की जरूरत थी. रिसर्च के लिए बड़ी संख्या में बंदरों को लैब में रखा गया था. ऐसे ही एक लैब डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी थी. जहां 1958 में रखे बंदरों में अजीब बीमारी देखी गई. इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे. ये बंदर मलेशिया से कोपेनहेगन लाए गए थे. जब इन बंदरों की जांच की गई, तो इनमें एक नया वायरस निकला. इस वायरस को नाम दिया गया- मंकीपॉक्स.

जिसने अब दुनियाभर में टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि अब ये मामले 2023 के बाद 2024 में भी इंसानों में भी ज्यादा देखने को मिल रहे है, बता दें मंकीपॉक्सए का पहला मानव मामला 1970 में कांगो में सामने आया था, और तब से इस वायरस का प्रकोप जारी है. वर्तमान प्रकोप, कांगो का अब तक का सबसे खराब प्रकोप, जनवरी 2023 से अब तक 27,000 मामले और 1,100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे शामिल हैं.

WHO ने घोषित किया हेल्थ इमरजेंसी

हालांकि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है. अमेरिका, पकिस्तान, अफ्रीका, स्वीडन और सऊदी अरब सहित अब तक 13 अफ्रीकी देशों में मंकीपॉक्स के मामले देखे जा चुके हैं, जिसके चलते भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकीपॉक्स सुनकर बंदरों से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर एक बार इंसानों से इंसानों में किसी वायरस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, तो फिर जानवरों का रोल काफी कम हो जाता है.

क्या है मंकीपॉक्स ?

Mpox एक तरह का वायरस है जो इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है. ये चेचक के जैसे ही होती है, लेकिन इसके लक्षण कम गंभीर होते हैं. इस बीमारी में बुखार, थकान, शरीर में दर्द और त्वचा पर दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. ज्यादातर मामलों में ये बीमारी हल्की होती है लेकिन कुछ मामलों में गंभीर भी हो सकती है.

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स ?

कहा जाता है कि ये व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है. ये स्कीन के घावों, संक्रमित व्यक्ति के पास सांस लेने या संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई वस्तुओं जैसे बिस्तर, कपड़े और तौलिये के संपर्क में आने से फैल सकता है.

मंकीपॉक्स के लक्षण

लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में ठंड लगना, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, स्कीन पर मोटे दाने शामिल हैं. दाने आमतौर पर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं.

मंकीपॉक्स से बचाव के उपाय

- साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
- संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें.
- अगर स्कीन पर कोई घाव है तो उसे ढककर रखें.
- जानवरों के संपर्क में आने से बचें.
- सुरक्षित यौन संबंध बनाएं.
- क्षेत्र में प्रकोप है तो टीकाकरण करवाएं.
- बंदर, चूहे, छछूंदर, वानर प्रजाति के अन्य जीवों से दूर रहें
- विदेश से आए बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें

रिपोर्टस के मुताबिक, जिन लोगों को छोटी चेचक या चिकनपॉक्स हो चुका है या इससे संबंधित टीका (वैक्सीन) लग चुका है, उनमें इस बीमारी के होने का खतरा ना के बराबर है.

किसे होता है खतरा ज्यादा ?

बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, प्रग्नेंट महिलाओं को अधिक खतरा रहता है. इन्हें संक्रमण होने के बाद बीमारी सीवियर हो सकती है. इसलिए संक्रमित मरीज की पहचान के बाद उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखना चाहिए. कई लोगों में इसका संक्रमण निमोनिया और मेननजाइटिस कर देता है और बाद में सेप्टीसीमिया बन जाता है, जिसमें मौत का खतरा ज्यादा होता है. फिलहाल अफ्रीका में मंकीपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये बीमारी अन्य देशों में भी फैलने लगी है. भारत सरकार ने भी इस पर नजर रखना शुरू कर दिया है. इसलिए जरूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. अगर आपको मंकीपॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.

कब तक शहर-शहर होंगी 'निर्भया' दरिंदगी का शिकार?

शहर बदले, तस्वीर बदली लेकिन अगर कुछ नहीं बदले तो वो हैं हालात. दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जो गुस्सा और जो उबाल देश में उठा उसने एक आस जगाई थी की देश में अब कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी. अब किसी बेटी की आबरू नहीं लुटेगी. अब कोई मां इंसाफ की भीख नहीं मांगेगी. लेकिन सब बेईमानी साबित हुआ. हफ्ते, महीने, साल बदले, सरकारें बदलीं. अधिकारी बदले पर हालात जस के तस रहे. कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक. जयपुर से लेकर बदलापुर तक कहानी एक जैसी है. जो सिस्टम को आईना दिखा रही है, अधिकारियों के दावे बड़े- बड़े हैं, वर्दी पर बड़े- बड़े स्टार हैं. लेकिन सब पर ढेरों सवाल खड़े होते है,

दरअसल पिछले कई दिनों से रेप के मामलों ने पूरे देश में गुस्सा है, एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे है. कोलकाता कांड ने तो सबको झकझोंर कर रख दिया, जिसने न सिर्फ लोगों का गुस्सा भड़का बल्कि बहुत से लोगों ने आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग उठा दी. लेकिन ठीक ऐसा ही एक मामला या यूं कहें कि इससे भी खौफनाक वारदात

कोलकाता से 1357 किलोमीटर दूर उत्तरखंड के रुद्रपुर में अंजाम दी गई. जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ. पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे. ये मामला है एक नर्स के साथ रेप और हत्या का. जिसे जानकर हर कोई सकते में है. ये खौफनाक वारदात है ऊधम सिंह नगर जिले के रूद्रपुर की, जहां एक बड़ा निजी अस्पताल है. जिसमें एक नर्स काम करती थी. वो रोज अपने तय वक्त पर अस्पताल जाती थी और वापस घर आती थी. 30 जुलाई को भी वो अपने घर से समय पर निकली थी.

लेकिन शाम हो जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी. जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग सका और फिर एक दिन 8 अगस्त को यूपी के रामपुर जिले की बिलासपुर थाना पुलिस को वसुंधरा एनक्लेव रोड पर झाड़ियों में एक कंकाल बन चुकी लाश मिली. ये इलाका एक्टिवा बिलासपुर के तहत आता है. वो लाश जिस हाल में मिली थी, उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल था. क्योंकि उसका चेहरे की खाल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी. खोपड़ी साफ नजर आ रही थी. हैरानी की बात ये थी कि पूरी लाश कंकाल बन चुकी थी, लेकिन उसके हाथ और पैर सही दिख रहे थे. पुलिस ने जब वहां आस-पास छानबीन की और तलाशी ली तो वहां से एक महिला का आईडी कार्ड पुलिस को मिला. वो आईडी कार्ड नर्स का ही था. जिसने सबको हैरान करके रख दिया,

ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे देश में कई मामले सामने आ चुके है. जिसने समाज पर भी सवालिया निशान लगा दिए है. आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है. ये संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रखे गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से ली गई है. अब बच्चियों की आबरू लूट रही है सिस्टम सोया पड़ा है अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं. अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो बस इंसाफ की मांग. कहने को तो लॉ-एंड- ऑर्डर चकाचक हैं. कहने को सूबे में बड़े-बड़े अधिकारी है जिलों में बड़े-बड़े जिम्मेदार पढ़े- लिखे आईएएस- पीसीएस अधिकारी हैं. लेकिन सब तमाशबीन बने हुए हैं. तमाशा सिस्टम की मक्कारी का. तमाशा परिवारों की बेबसी का. तमाशा बेटियों की इंसाफ मांगती चीखों का और तमाशा बेबसी का. सवाल है कि आखिर कब तक. शहर- शहर कितनी निर्भया दरिंदगी का शिकार होंगी. आखिर अधिकारियों की नींद कब टूटेगी. शहरों से लेकर गांव की गलियों तक में बेटियां कब महफूज रहेंगी. आज ये सवाल हर कोई पूछ रहा है.

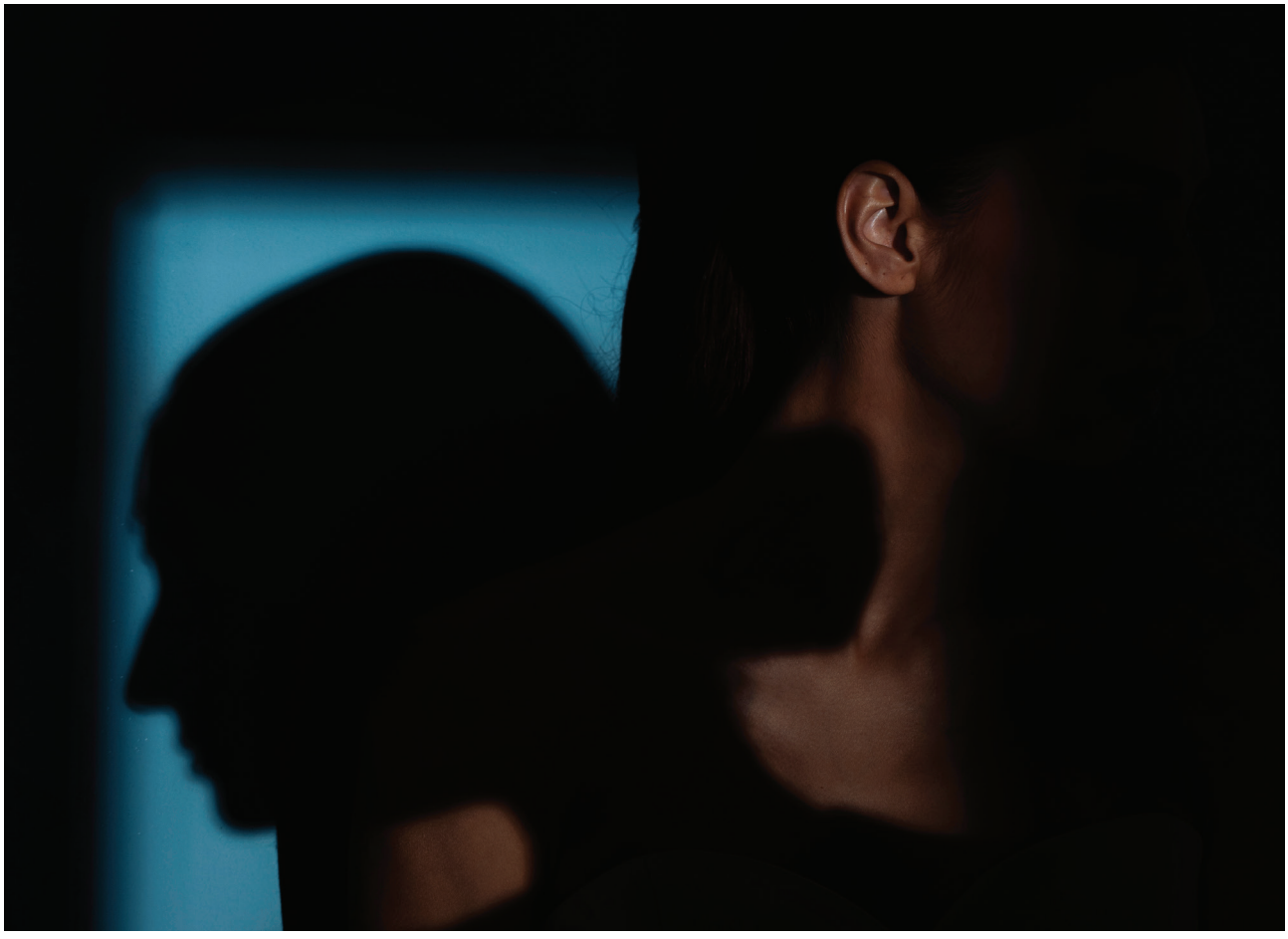

मूंछों वाले 'गब्बर' ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, कैमरे पर बताई अपने दिल की बात

अचानक टीम इंडिया के 'गब्बर' कहे जाने वाले स्टार क्रिकेटर शिखर धवन ने एक वीडियो पोस्ट कर क्रिकेट से संन्यास ले लिया. जिसने फैंस को बड़ा झटका दिया. शिखर धवन पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे. 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला था, तब से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी. हालांकि अब संन्यास के बाद रोहित ने बहुत बड़ी दिल छूने वाली बात कही है.

'केवल यादें ही नजर आती हैं'

24 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए धवन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया. धवन ने वीडियो में कहा कि आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं, जहां से पीछे देखने पर केवल यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर पूरी दुनिया. मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना. वो पूरा भी हुआ. इसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं, सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच जिनके अंडर में मैंने क्रिकेट सीखी. टीम इंडिया में खेलने के बाद मुझे आप फैन्स का प्यार मिला. लेकिन वो कहते हैं ना कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है. बस मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूं. मैं अपने क्रिकेट के सफर के इस अध्याय को समाप्त कर रहा हूं, मैं अपने साथ अनगिनत यादें और कृतज्ञता लेकर जा रहा हूं. प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद! ये वीडियो सामने आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई.

लंबे समय से BCCI कर रहा था नजरअंदाज

शिखर धवन ने भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन, 167 वनडे मैचों में 6793 रन और 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1759 रन बनाए हैं. लेकिन अब कभी वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे और रोहित के साथ ओपनिंग की जोड़ी भी अब नहीं देखेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार धोनी ने रोहित और शिखर धवन को ओपनिंग करने के लिए उतारा था. तभी से ये दोनों भारत की बल्लेबाजी की नींव बन गए थे. इन्होंने मिलकर टॉप ऑर्डर में ढेरों रन कूटे थे. रोहित के साथ धवन ने दुनिया के हर मैदान में रन बनाए थे. बड़े से बड़े गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी देखकर दांतो तले उंगलियां दबा लेते थे. सेलेक्टर्स शिखर धवन को लंबे समय तक नजरअंदाज कर रहे थे, जिसके चलते वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने को मजबूर हुए.

2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में रहा अहम रोल

रोहित शर्मा की तरह ही शिखर धवन तूफानी बैटिंग में माहिर थे. शिखर धवन को टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था, भारत ने साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें शिखर धवन का बड़ा रोल रहा था. इसमें सबसे ज्यादा 363 रन धवन ने ही बनाए थे. इतना ही नहीं शिखर धवन IPL में बैक-टू-बैक शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड धवन के नाम है. दिल्ली के रहने वाले धवन एक आक्रामक बल्लेबाज थे, जो गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में मशहूर थे. अपनी घुमावदार मूंछों से नया स्टाइल स्टेटमेंट बनाने वाले धवन का कैच लपकने के बाद जांघों पर हाथ मारने का सिग्नेचर स्टाइल हमेशा याद रखा जाएगा. हालांकि वो IPL खेलेंगे या नहीं, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है.

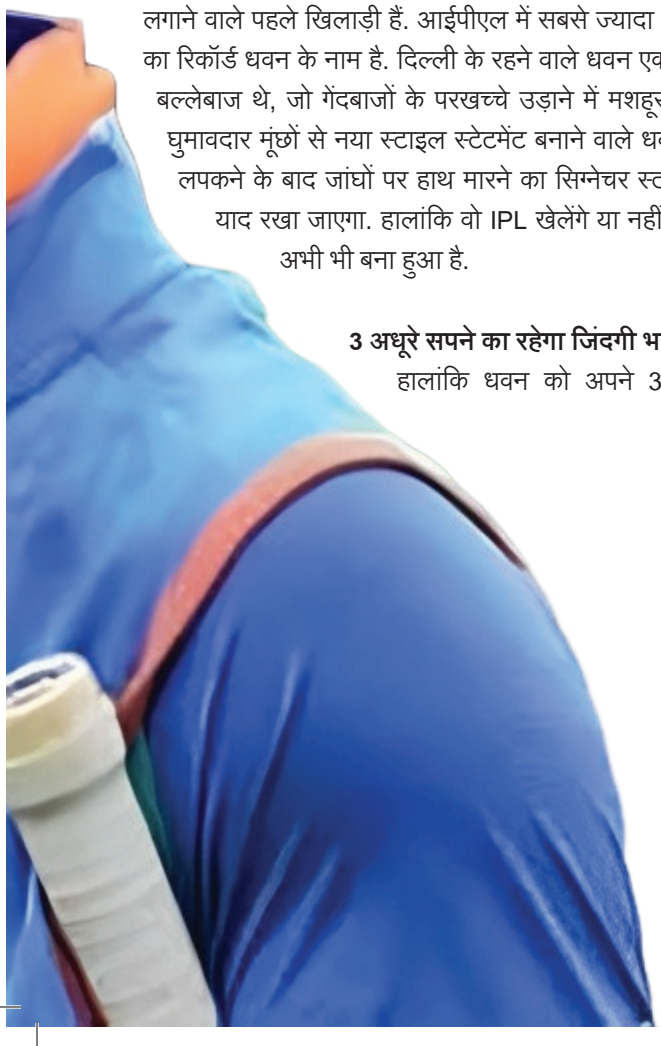

3 अधूरे सपने का रहेगा जिंदगी भर मलाल

हालांकि धवन को अपने 3 सपने का

मलाल जिंदगी भर रहेगा जिन्हें वो पूरा नहीं कर सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक गब्बर को माही की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली, इसके बाद टीम की कमान कोहली ने संभाली. रोहित की कप्तानी में भी धवन ने अपना जौहर दिखाया, लेकिन खुद कभी उन्हें फुल टाइम कैप्टेंसी नहीं मिली जबकि उनके पास IPL में कप्तानी का लंबा अनुभव था. गब्बर को जून 2021 में श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और टी-20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. युवा खिलाड़ियों से सजी इस टीम में कई सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन ये जिम्मेदारी अस्थायी थी. वहीं दूसरे सपने की बात करें तो 2004 अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने धवन को भले ही मिस्टर ICC कहा जाता हो, लेकिन वो कभी भी भारत के लिए कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए. भारत के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और टी-20 वर्ल्ड कप जैसे तीनों फॉर्मेट में खेलने के बाद भी उन्हें कभी ट्रॉफी उठाने का सौगाभ्य नहीं मिला. जबकि तीसरा सबसे भावुक होने वाला सपना है, कहा जाता है कि हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो अपने करियर की शुरुआत और अंत धमाकेदार अंदाज में करे. जब आए तब दुनिया उसका नाम याद कर ले और जब करियर का अंत करे तो पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंजने लगे. मगर युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़ सरीखे दिग्गजों की तरह शिखर धवन को भी रिटायरमेंट मैच खेलने का नसीब नहीं मिला. मैदान से सम्मानजनक विदाई भी नहीं मिली, जिसका मलाल उनको ताउम्न रहेगा.

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावी समीकरण

जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है. जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होगा. वहीं, हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा. दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे. जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर, दूसरे चरण 26 सीटों पर और तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा.

चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बीर 3 सीटें बढ़ाई गई हैं. पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थीं. वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, एथलीट और खिलाड़ियों की धरती में 2 करोड़ 1 हजार वोटर हैं. राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 20 हजार 629 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. यहां 73 सामान्य सीटें और 17 एससी सीटें हैं. इसकी वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी कर दी जाएगी. हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है. हरियाणा में वर्तमान में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं. यहां पर 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे.

जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहा चुनाव

जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था. तब से अब तक दस साल के दरमियान काफी कुछ बदल गया है. धारा 370 और 35-ए के निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफी बदला है. जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रशासित प्रदेश

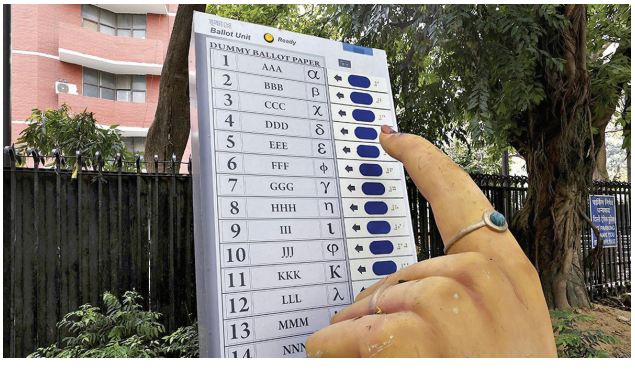

है. हालांकि, यह स्टेटस अस्थायी है. 2019 अगस्त में केंद्र सरकार ने 5-6 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के लिए विधेयक पारित किया था, और इस दो हिस्सों में बांटकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था.

विधानसभा में बढ़ाई गई 7 सीटें

केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदली गई हैं. हालांकि, सात सीटें विधानसभा में जोड़ी गई हैं, जिनमें छह जम्मू डिवीजन में हैं और एक सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है. एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थीं, और दो महिला सदस्यों को नामित करने का प्रावधान था. अब साथ ही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 विधानसभा की सीटें फ्रीज और खाली थीं. लेकिन अब जम्मू - 37 सीटें, कश्मीर - 46 सीटें, लद्दाख- 4 सीटें हैं।

विस्थापित कश्मीरी पंडितों को मिलेगा मौका

विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने दो विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी विधायक के तौर पर नामित किए जाने का प्रावधान किया है. इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित समुदाय के एक सदस्य और दो महिलाओं को भी विधायक के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। इस हिसाब से यहां विधानसभा में 95 सीटें हो गई हैं।

जम्मू डिवीजन की राजनीति और रणनीति

बता दें कि अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में किए गए परिसमन में जम्मू डिवीजन को राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया है. इस क्षेत्र में छह नई सीटें जोड़ी गई हैं, जो को रणनीतिक रूप से बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जम्मू डिवीजन में परिसीमन से पहले 37 सीटें थीं, जो अब 43 हो गई हैं.

जम्मू डिवीजन में हमेशा से यह शिकायत रही है कि कश्मीर घाटी से ज्याजा बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद विधानसभा में यहां के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है. काफी हद तक यह शिकायत दूर हुई है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी स्थानीय पार्टियों ने इसको लेकर आरोप भी लगया कि परिसीमन की कवायद बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है.

हरियाणा में किसकों कितनी सीटें

हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान में तीन सीटें खाली हैं। बीजेपी के 41 विधायक हैं। कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और INLD और HLP के एक-एक विधायक हैं। सदन में पांच निर्दलीय विधायक हैं।

2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राज्य की कुल 90 सीटों में से बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिलीं। इसके अलावा जननायक

जनता पार्टी (जेजेपी) को 10 सीटें और अन्य को 9 सीटें मिली थी। बाद में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।

बीजेपी की राह नहीं होगी आसान

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है, अगर विधानसभा चुनाव में भी यह ट्रेंड जारी रहा तो बीजेपी का सत्ता में वापस आने का सपना टूट सकता है। बीजेपी अपने दम पर 2014 और 2019 में राज्य में अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन इस बार की राह उसकी आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में कई चुनौतियां लेकर सामने आ रही है। इसमें किसानों का मुद्दा काफी अहम है। कृषि कानूनों के विरोध में चले किसान आंदोलन का हरियाणा में अच्छा-खासा प्रभाव रहा था और बीजेपी को वहां लोकसभा चुनाव में भी किसान राजनीति वाली बेल्ट में काफी नुकसान उठाना पड़ा था।

बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल यह है कि जाटों की नाराजगी कैसे दूर करें। जाट समुदाय की हरियाणा में आबादी 25% तक है और इतने बड़े समुदाय की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकता है। पिछले साल जब महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था तो हरियाणा में काफी विरोध हुआ था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हरियाणा में जाट समुदाय की नाराजगी को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था लेकिन उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया और वह जीत कर सांसद बने हैं।

महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चित रहा था। ऐसा में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा नाराजगी झेलना पड़ सकता है।

जाट राज्य की आबादी का लगभग 27 फीसदी हिस्सा हैं

जाट राज्य की आबादी का लगभग 27 फीसदी हिस्सा हैं। ये 2014 तक राज्य की राजनीति पर हावी रहे। उसी वर्ष बीजेपी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से सात पर जीत हासिल की और कुछ महीनों बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसमें पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा और केंद्र में यूपीए के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना और नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव इस बदलाव के प्रमुख कारक थे।

ECOTECH PROPERTIES

Industrial, Commercial & Residential Plots Sale & Purchase
E-mail: maheshecotech@gmail.com

Construction | Functional | S.S.I. | Compilation & All Work

Mahesh Kumar: 9810172004

Head Office Ecotech 6 A 48 Greater Noida Gautam Buddh Nagar
Office-Ecotech 3 UK 2 448 Greater Noida Gautam Buddh Nagar (U.P)

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW

2nd Edition

Date : 25th - 29th September, 2024

Venue : India Expo Centre & Mart, Greater Noida

दुनिया देखेगी यूपी का जलवा

आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन कारोबार की दृष्टि से इसका स्थान सबसे आगे नहीं है। लेकिन अब औद्योगिक विकास की राह पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक से बढ़कर एक कीर्तिमान उत्तर प्रदेश रच रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश को भारत के नया ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी तो यूपी इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। प्रदेश को आर्थिक गति पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है, राज्य में इंवेस्टमेंट फ्रेंडली नियम बनाए जा रहे हैं। अगर प्रदेश की आर्थिक रफ्तार में गति पकड़ानी है तो उद्योग और उद्यमियों को बढ़ाने का काम सबसे पहले होना चाहिए। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार "यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो" का एडिशन टू इसी महीने 25 से 29 सितंबर तक आयोजित करने जा रही है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इस महीने से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भव्य व्यापारिक मेला "यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो" का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश-विदेश के व्यापारियों और ग्राहकों को उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। इस मेले का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी होंगे, जो विश्व के 80 से अधिक देशों से आने वाले खरीदारों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यह मेला न केवल स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण

इस ट्रेड शो के बारे में कुछ और बातें:

इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के हर ज़िले की खास चीज़ों को दिखाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की झलक दिखाई जाएगी.

खादी से बने परिधानों का फैशन शो होगा.

वियतनाम की सांस्कृतिक मंडली भी आएगी.

गाज़ियाबाद के उद्यमी भी अपने उत्पादों को दिखाएंगे.

बनारस के पारंपरिक कारीगरों के हुनर और आधुनिक उत्पादों को भी दिखाया जाएगा.

इसके अलावा ट्रेड शो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गाज़ियाबाद में बने इंजीनियरिंग गुड्स को भी दिखाया जाएगा.

मंच साबित होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस बार ट्रेड शो में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा,जिससे वे व्यावसायिकता और उद्यमिता का अनुभव कर सकें। इसके अलावा सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) को भी मेले में जोड़ा जाएगा। इससे इस आयोजन का अधिकतम लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की तैयारी है। मेले में आने वाले लोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मशहूर व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए एक बड़े फूड कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ की बिरयानी और कवाब, मेरठ की नानखटाई, कानपुर के ठग्गू के लड्डू, गोरखपुर का मोछू का छोला, सहारनपुर का भरवा चिकन कोफ्ता, मुजफ्फरनगर की चाट और अन्य कई स्थानीय व्यंजन उपलब्ध होंगे। इस पहल से न केवल उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का प्रचार-प्रसार होगा। बल्कि यह प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर को भी बढ़ावा देगा। जिससे भविष्य में निवेश और उद्योगों का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के उत्पाद प्रदर्शनी के लिए रखे जाएंगे। जिससे व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो न केवल उत्तर प्रदेश के व्यापारिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है,बल्कि यह राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

सर्वाधिक अफ्रीकी रीजन से हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन

जिन देशों ने अब तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें सबसे ज्यादा 14 देश अफ्रीका रीजन के हैं। इसके अलावा 12-

12 देश यूरोप और वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से हैं। इसके अलावा 8 देश लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन से हैं। सात देश कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 5 देश साउथ ईस्ट एशियन रीजन, 4-4 देश साउथ अफ्रीकन और नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं।

पहले एडिशन से कहीं अलग होगा ट्रेड फेयर का दूसरा संस्करण

साल 2023 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हुआ था, वैसे तो पहला संस्करण पूरी तरह से हिट रहा था, लेकिन यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण हर मायने में बिल्कुल अलग होने जा रहा है। ट्रेड शो के पहले एडिशन में दो हजार एग्जिबिजर्स ने अपनी प्रदर्शनी लगाई

डीएम मनीष कुमार ने दी ये जानकारी

आगामी 25 सितंबर से लगने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में डीएम मनीष कुमार ने जानकारी दी कि ग्रेटर नोएडा में दूसरी बार लगने जा रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पिछली बार की अपेक्षा बड़े स्तर पर होगा। इस बार ट्रेड शो में इंग्जीबिटर्स, बिजिटर्स और बॉयर्स को बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इस ट्रेड शो का मकसद यूपी के प्रोडक्ट्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिलवाना है। इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कई खास इंतजाम किये गये हैं। इस ट्रेड शो में आम लोगों के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। डीएम ने बताया कि इस बार लोकल उत्पातों को एक बेहतरीन मौका दिलवाया जाएगा। ताकि उनका व्यापार ना सिर्फ तरक्की कर सके, बल्कि दुनिया के बाजार में उनका भी दखल हो।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले एडिशन की बात करें तो पांच दिनों में तीन लाख से ज्यादा लोगों ने यहां विजिट किया था। जबकि इस बार अनुमान है कि इससे कहीं ज्यादा 5 लाख लोगों की यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को विजिट करने की उम्मीद है। जिसमें विजिटर्स,बॉयर्स और इंग्जीबिटर्स शामिल होंगे। इस बार 80 देशों के स्टॉल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देखने को मिल जाएंगे। ट्रेड शो में 11 बजे से तीन बजे तक बीटूबी और तीन बजे के बाद आम लोगों के लिए एग्जिबिशन खोला जाएगा।

थी। जबकि दूसरे संस्करण में 2500 एग्जिबिटर्स प्रस्तावित हैं। इस बार बिजनेस टू बिजनेस में एक लाख से अधिक विजिटर्स की आने की उम्मीद है, जबकि पहले संस्करण में यह संख्या 70 हजार थी। इसी तरह बिजनेस टू कस्टमर में 3.5 लाख से अधिक विजिटर्स लाने का प्रस्ताव है जो 2023 में 2.37 लाख था। इसी तरह 2023 में जहां एक लाख से अधिक नए व्यापारिक सूत्रों का उद्भव देखने को मिला था तो वहीं इस बार ये संख्या 1.25 लाख प्रस्तावित है। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के बड़े उद्योगों, आईटी, आईटीईएस, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और उर्जा, ओडीओपी जैसे सेक्टर्स के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध करवाएगा।

कृषि विभाग लगाएगा प्रदर्शनी

इस प्रदर्शनी में प्रदेश का कृषि विभाग 1000 स्क्वायर मीटर में स्टाल लगाएगा. इस प्रदर्शनी के जरिए ट्रेड शो में आए हुए मेहमानों को उत्तर प्रदेश की उन्नत कृषि संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के प्रगतिशील किसान व कंपनियां भी शामिल होंगी. इसमें लगभग दो दर्जन से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) हिस्सा लेंगे. बता दें कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए जोरों पर तैयारियां चल रही हैं.

काशी के पारंपरिक हस्तशिल्प का दुनिया देखेगी जलवा

इतिहास से भी प्राचीन होने का गर्व संजोने वाली काशी जितना आध्यात्म, धर्म, परंपरा और संस्कृति के लिए जानी जाती है, लेकिन काशी की पहचान उसके पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों से भी पूरे विश्व में है। काशी की प्राचीन, पारंपरिक हस्तशिल्प व आधुनिक उत्पाद ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रंग बिखेरने के लिए तैयार है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विश्व भर से आने वाले खरीदार बनारस के परंपरागत कारीगरों के हुनर और आधुनिक उत्पादों को देखेंगे। इससे हस्तशिल्पियों समेत अन्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मिलेगा।

वाराणसी से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, निर्यातकों समेत सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्योग के 29 उद्यमियों ने लोकल से ग्लोबल मार्केट में अपना उत्पाद ले जाने के लिए पंजीकरण करा चुके है। पंजीकरण के अभी और बढ़ने की संभावना है।

गाज़ियाबाद के 70 से अधिक उत्पादों की दिखेगी झलक

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) को लेकर जिले के उद्यमियों में खासा उत्साह है। ट्रेड शो के दूसरे एडिशन में कुछ उद्यमी लगातार दूसरी बार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं, कुछ उद्यमी इसमें पहली बार अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। देश-विदेश से आने वाले खरीदार ट्रेड शो में पहुंचेंगे। जिले की 70 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्टाल की बुकिंग कराई है। इनमें इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रानिक और कास्मेटिक उत्पाद शामिल हैं। गत वर्ष ट्रेड शो में जिले के 60 उद्योगों ने प्रतिभाग किया था। इससे उद्योगों के उत्पादों की देश-विदेश के खरीदारों के बीच अच्छी मार्केटिंग होने के साथ ही कई बड़े ऑर्डर भी मिले थे। उद्यमियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी उद्यमियों को अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिलेगा। जिले के उद्यमी अपने आधुनिक इंजीनियरिंग उत्पाद को देश-विदेश से आने वाले निर्यातकों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गाजियाबाद के इंजीनियरिंग गुड्स को ट्रेड शो में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा जिले के उद्यमी अपने अन्य उत्पादों को भी ट्रेड शो में प्रदर्शित करेंगे।

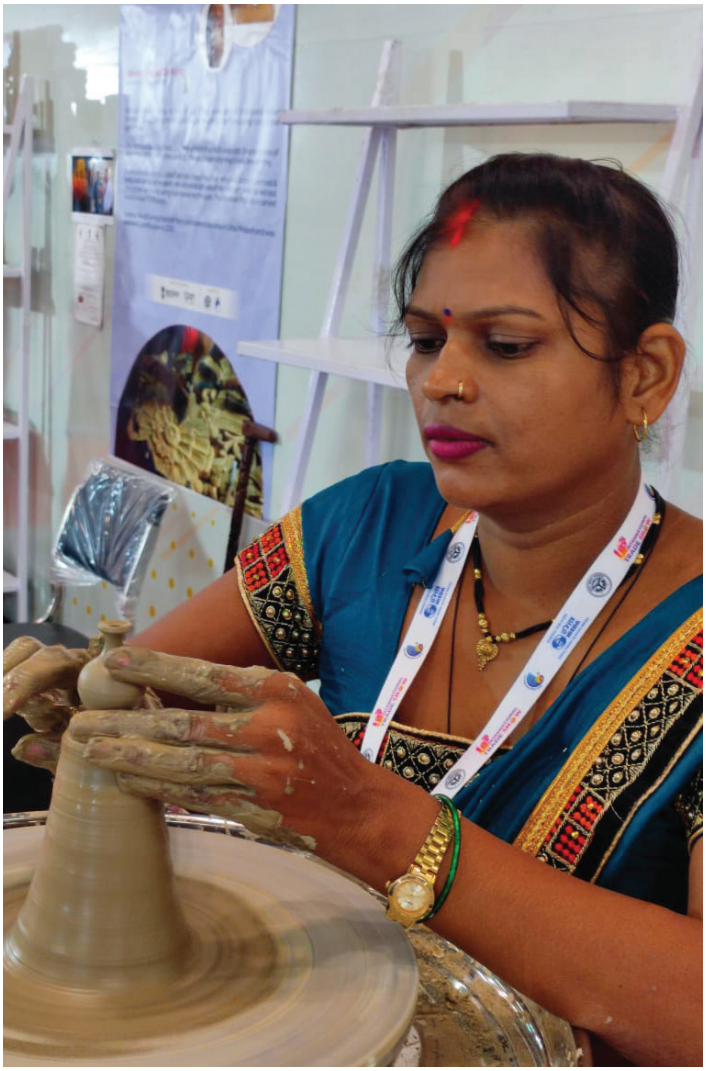

राज्य के फेमस व्यंजन मिलेंगे

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे एडिशन में बहुत कुछ नया दिखने वाला है। पिछले साल लगे ट्रेड शो की कुछ खामियों से सबक लेते हुए कई तरह के सुधार ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट प्रबंधन ने किये हैं। इस बार प्रदेश के कल्चरल प्रोगाम को भी दर्शाने की पूरी तैयारी है। ये कलाकार 80 देशों से आने वाले विजिटर्स और बॉयर्स के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा जायके के लिए अलग से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां जाकर प्रदेश के अलग-अलग व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। दुनिया भर के लाखों बिजिटर्स, बायर्स और इंग्जीबिटर्स ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंचने वाले हैं। जिनके लिए इस बार खास इंतजाम जिला प्रशासन और इंडिया एक्सपो मार्ट प्रबंधन की तरफ से किया गया है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि मेहमानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बस के इंतजाम के अलावा, रहने, खाने की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेड फेयर यूपी के लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। यूपी के कई क्षेत्रों से आने वाले लोगों को यहां के फूड कोर्ट में अपनी मिठाई और अन्य व्यंजन बेचने का मौका मिलेगा। यहां मिलने वाले व्यंजनों में आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, मेरठ की नानखटाई. लखनऊ के कबाब और बिरयानी, गोरखपुर का मोछू का छोला व मुजफ्फरनगर की चाट के साथ कई अन्य क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों का टेस्ट भी दुनिया भर से आने वाले लोग लेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का बनेगा भव्य पवेलियन

UP News योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बड़ी तैयारी कर रही है। वहीं 25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट प्रतिभाग करेगा। सीएम योगी के विजन के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बढ़ती सहभागिता और सेक्टर फेवरिंग नीतियों को वृहद स्तर पर

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश की व्यापक उपस्थिति को अब बड़े स्तर पर दर्शाने जा रही है। देश-विदेश के निवेशकों का प्रदेश में कार्यरत आईटी सेक्टर के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने और इस परिदृश्य में निवेश आकर्षित करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण निभाएगी।

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में इन्फॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमिकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स के बड़े क्लस्टर्स कार्यरत हैं, जबकि निकट भविष्य में और कई क्लस्टर्स के स्थापना की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बढ़ती सहभागिता और योगी सरकार द्वारा सेक्टर फेवरिंग नीतियों को वृहद स्तर पर शोकेस करने के लिए उत्तर प्रदेश आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भव्य पवेलियन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिका इंडिया व यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सहभागिता करने जा रही है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने इस क्रम में एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फेज 2 में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे इन आयोजनों में पहले 11 से 13 सितंबर के बीच इलेक्ट्रॉनिका इंडिया का आयोजन होगा, जबकि 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में

इन दोनों आयोजनों में सीएम योगी के विजन के अनुसार, उत्तर प्रदेश आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग पवेलियन के माध्यम से अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है।

यहां वह योगी सरकार द्वारा सेक्टर फैवरिंग पॉलिसीज, कार्यरत क्लस्टर्स और उनकी उपलब्धियों के साथ ही भविष्य में स्थापित होने वाले क्लस्टर्स के बारे में भी जानकारियों को साझा करेंगी। यहां सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज सेशन, पार्टनर कंट्री सेशंस, बी2बी/बी2जी/जी2जी बैठकें, नेटवर्किंग मीट के साथ ही नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के वैश्विक तकनीक व उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

सेमिकॉन इंडिया द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिका इंडिया कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 145 स्क्वेयर मीटर क्षेत्र प्रसार वाले पवेलियन की स्थापना व संचालन होगा। जबकि, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड द्वारा आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 100 स्क्वेयर मीटर एरिया क्षेत्र में पवेलियन की स्थापना की जाएगी।

वहीं, यह पवेलियन ग्राउंड फ्लोर के हॉल नंबर-5 में स्थापित किया जाएगा और इसे डिजिटल डिस्प्ले, वीवीआईपी लाउंज, कॉफी वेंडिंग मशीन्स, एलईडी वीडियो वॉल्स व डिस्प्ले जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। यह इंटरैक्टिव स्क्रीन्स व क्रिएटिव कॉन्टेंट बेस्ड कॉन्सेप्च्युलाइज्ड थीम के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा।

लगातार छठवीं बार बसपा की अध्यक्ष बनीं मायावती

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल पांच साल होगा। इनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया, जो सर्वसम्मति से मंजूर हो गया। वहीं, नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है।

बता दें कि मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दिल्ली में ही प्राप्त की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त की। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1984 में की, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) जॉइन की। उनकी

शुरूआत बसपा के संस्थापक कांशीराम के नेतृत्व में हुई थी। मायावती ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम से मुलाकात की। कांशीराम ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दलितों, आदिवासियों, और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए BSP की स्थापना की थी। मायावती ने कांशीराम के नेतृत्व में BSP में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पार्टी की विचारधारा और उद्देश्यों को अपनाया और पार्टी की गतिविधियों में भाग लिया। मायावती ने 1984 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम किया और उनके राजनीतिक कौशल और समर्पण ने उन्हें पार्टी में एक प्रमुख भूमिका दिलाई। 1985 में मायावती को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी और उनके करियर की शुरुआत का संकेत था।

मायावती ने 1985 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। इसके बाद, उनकी राजनीति में कद बढ़ता चला गया। मायावती ने पहली बार 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और उनकी पार्टी ने 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त किया। उनके नेतृत्व में, BSP ने कई प्रमुख सामाजिक और विकासात्मक पहलों को लागू किया।

संघर्ष और विवाद

मायावती के कार्यकाल में कई विवाद भी रहे, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप और उनकी नीतियों पर आलोचनाएं। इसके बावजूद, उन्होंने सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। 2012 में, BSP को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2017 में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मायावती ने 2019 और 2024 के आम चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके नेतृत्व में BSP को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मायावती का राजनीतिक करियर समाज के पिछड़े वर्गों के लिए उनके संघर्ष और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। उनकी स्थिति और प्रभाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहे हैं।

मूसा मूनीर खान | लेखक

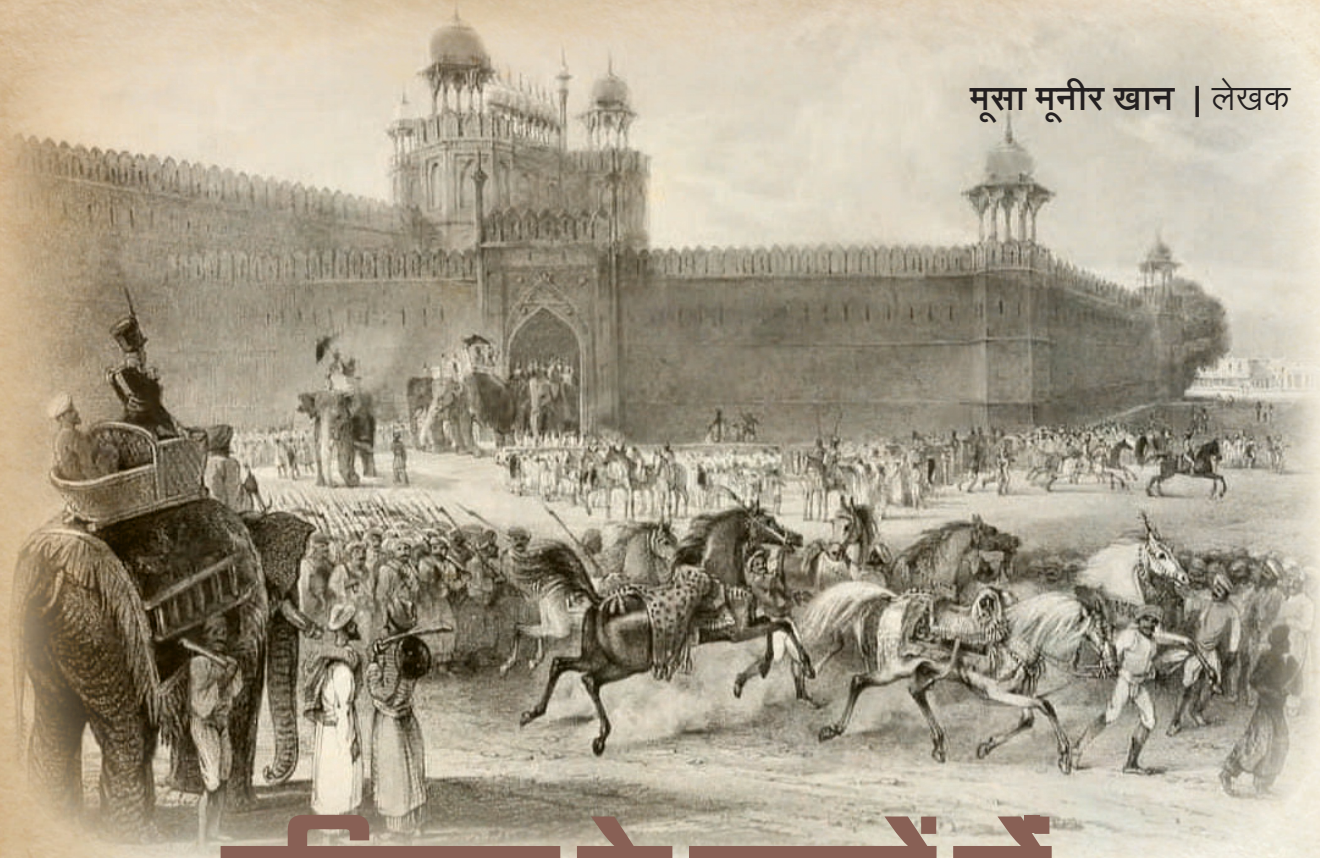

इतिहास के पन्नों में "बारह बस्तियाँ"

बारा बस्ती (Bara Basti) का नाम सुनते ही इतिहास के पन्नों में झांकने की इच्छा जागृत हो जाती है। बारा बस्ती का अर्थ "बारह बस्तियाँ" होता है, जो आज के बुलंदशहर, गाजियाबाद, और अमरोहा जिलों में स्थित हैं। इन गांवों का इतिहास मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल तक जाता है। इस इतिहास की शुरुआत होती है बासी बागर नामक गांव से, जिसे दाउदज़ाई अफगान सरदार के पुत्र शेख रुकनुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे स्थापित किया था। यह गाँव एक छोटे से ठिकाने से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना।शेख रुकनुद्दीन की वीरता के कारण उन्हें मुगल शासकों द्वारा सम्मानित किया गया, और उन्हें मानसबदार की पदवी प्राप्त हुई।

शेख रुकनुद्दीन की वीरता और उनकी धरोहर

शेख रुकनुद्दीन को उदयपुर के राणा अमर सिंह के खिलाफ युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए "शेर खान" की उपाधि से नवाजा गया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी एक भुजा गंवा दी, लेकिन उनकी वीरता को सम्राट जहांगीर ने न केवल पहचान दी, बल्कि उन्हें पेशावर की जागीर और गुजरात सरकार का परगना भी सौंपा। उनके निधन के बाद, उनकी जागीर का एक हिस्सा और उपाधियाँ उनके भाई और बच्चों को सौंप दी गईं। उनके पुत्र, शेख कमालुद्दीन दाउदजाई, ने जहांगीर के शासनकाल में मानसबदार के रूप में सेवा की, लेकिन बाद में उन्होंने खानजहां लोधी के साथ मिलकर शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया.

खानपुर का उदय और शेख अल्लू अफगान की भूमिका

शेख अल्लू अफगान, जो शेख कमालुद्दीन के छोटे भाई थे, उन्हें भी मुगल मानसबदार में शामिल किया गया और उन्हें विभिन्न अनुदान प्राप्त हुए। उन्होंने एक गांव की स्थापना की, जिसे उनके नाम पर "खानपुर" कहा गया। यहां उन्होंने एक बड़ा मिट्टी का किला, एक मस्जिद, और अन्य कई भवनों का निर्माण किया। इसी के चलते, खानपुर बारा बस्ती के गांवों का प्रशासनिक केंद्र बन गया। बारा बस्ती के गांवों में दाउदज़ाई अफगानों की बस्तियाँ शामिल थीं, जिनमें बासी बांगर ,बुगरासी, जलालपुर, चांदियाना, गेसुपुर, बड़वाला, अमरपुर, शेरपुर, बहादुरगढ़, हसनपुर, मोहम्मदपुर, और गिरौरा शामिल थे। शेख अल्लू अफगान का निधन हिमाचल प्रदेश के तारागढ़ के विद्रोही राजा जगत सिंह के खिलाफ युद्ध करते हुए था

। उनके अवशेषों को वापस खानपुर लाया गया, जहाँ उन्हें शाहजहां के शासनकाल में ताड़ के पेड़ के नीचे पक्की खबर बनाकर दफनाया गया।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में खानपुर Estate और बारा बस्ती (Bara Basti) की भूमिका

1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, खासकर खानपुर जागीर और ब्रिटिश सेना के बीच संघर्ष के संदर्भ में। नवाब मुस्तफा खान, जिन्हें शेफ्ता के नाम से भी जाना जाता है, को भीम सिंह गुरौली, बुलंदशहर द्वारा जहांगीराबाद किले से निष्कासित कर के खुद काबिज हो गया था। नवाब शेफ्ता ने खानपुर परिवार से सहायता मांगी, और हाजी मुनीर खान, आज़िम खान के पुत्र, अपनी असंगठित कैवलरी सेना के साथ, जिसमें मुख्य रूप से बारा बस्ती के पठान शामिल थे, नवाब की सहायता के लिए आगे आए। एक युद्ध हुआ जिसमें ठाकुर भीम सिंह को पराजित कर, हाजी मुनीर खान ने उन्हें जहांगीराबाद में दुबारा कायम कराया।

1857 के महान विद्रोह में खानपुर जागीर और बारा बस्ती (Bara Basti) की भूमिका

मुगल शासन के दौरान, बुलंदशहर जिले में केवल कुछ ही तालुकदार जागीरें थीं, जिनमें खानपुर छतारी, कुचेसर, पहासू, और शिकरपुर शामिल थीं। जब 1857 का महान विद्रोह शुरू हुआ, मेरठ शिविर में बहुत कम ताकत थी। ब्रांड साप्टे ने बुलंदशहर जिले के तालुकदारों को सैनिकों और घोड़ों की सहायता के लिए पत्र लिखा। इस अनुरोध का तत्काल सकारात्मक उत्तर मिला। हालांकि, खानपुर जागीर ने विद्रोह में शामिल होने का फैसला किया। नवाब वलीदाद खान ने दोआब में प्रवेश किया और बुलंदशहर जिले के प्रमुख तालुकदार से सहायता मांगी जिसमें मुख्य रूप से खानपुर रियासत ने अहम भूमिका निभाई और वही दादरी के राव उमराव सिंह भाटी और अमन गुर्जर जो बुलंदशहर के गुर्जरों के मुखिया थे उन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया और ज्यादातर बुलंदशहर के गुर्जरों ने खानपुर रियासत में पनहा ली और साथ मिलकर लड़े।

खानपुर रियासत परिवार के तीन लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और शहीद हुए

1: अजीम खान बुलंदशहर जिले के खानपुर नामक ऐतिहासिक तालुकदार एस्टेट से ताल्लुक था । 1857 के महान विद्रोह के बीच, नवाब वलीदाद खान ने अजीम खान को खुर्जा में अपना डिप्टी नियुक्त किया, जहां उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का विरोध किया, जिससे वे अस्थायी रूप से पंगु हो गए। रोहिलखंड में जाने के लिए गंगा पार करते समय उन्हें अनूपशहर के पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया। बाद में, उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें फाँसी दे दी गई।

2: अजीम खान के इकलौते बेटे हाजी मुनीर खान ने 1857 के महान विद्रोह के दौरान बुलंदशहर जिले में विद्रोहियों के मुख्य नेता के रूप में कार्य किया था। 29 जुलाई 1857 को गुलावठी की ऐतिहासिक दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने कमान संभालने का लक्ष्य रखा था। सम्पूर्ण बुलन्दशहर जिला. उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए, मालागढ़ के नवाब वलीदाद खान ने अपने मुख्य कमांडरों हाजी मुनीर खान और इस्माइल खान को गुलावठी भेजा। उन्होंने औपनिवेशिक सैनिकों को बुलन्दशहर जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए गुलावठी के पास नहर पर एक चौकी बनाई। दुखद बात यह है कि हाजी मुनीर खान और इस्माइल खान दोनों के चेहरे पर तलवार के गहरे घाव लगे। हाजी मुनीर खान, वलीदाद खान के साथ, बहादुरी से गंगा पार कर गए और खान बहादुर खान की सेना के साथ शामिल हो गए।

बाद में, हाजी मुनीर खान ने वलीदाद खान के साथ गंगा पार की और खुद को खान बहादुर खान रोहिल्ला की सेनाओं के साथ जोड़ लिया, जहां उन्हें खान बहादुर खान द्वारा नायब कोतवाल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में कछला घाट पर युद्ध में भाग लिया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे।

3:अजीम खान के भतीजे अब्दुल लतीफ खान, बुलन्दशहर जिले के दूसरे सबसे अमीर तालुकदार थे, जिनके पास कई सौ गाँव, थे जोकि जिला बदायूँ, मोरादाबाद, मेरठ और बुलन्दशहर जिले में होते थे। प्रारंभ में, अब्दुल लतीफ खान युद्ध के मैदान में कभी शामिल नहीं होने के बावजूद, अब्दुल लतीफ खान ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के दौरान बुलन्दशहर जिले के महान क्रांतिकारी जैसे नवुल गुर्जर, रहीमोद्दीन और बराह बस्ती गांवों के पठान को आश्रय प्रदान करके अपना समर्थन बढ़ाया। परिणामस्वरूप, उन्हें एक सैन्य अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा और 1857 के विद्रोह में सहायता करने के लिए उन्हें अंडमान या काला पानी ले जाने की आजीवन कारावास की सजा मिली। औपनिवेशिक ताकतों द्वारा 1857 के महान विद्रोह के दमन के बाद, खानपुर संपत्ति उस परिवार से जब्त कर ली गई, जिसका वह पहले स्वामित्व था।

1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सेना ने खानपुर जागीर को जब्त कर लिया और इसे और इसके बाद उनके सहयोगी रहे सैयद मीर खान बहादुर को खानपुर जागीर एवं किला बतौर इनाम दिया गया और उनके चाचा जान फिशा खान को सरदाना की जागीर मिली । इस परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था जिसके चलते अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि , पेंशन और जगीरो के इनाम दिए।

खानपुर जागीर की जब्ती और खानपुर परिवार का विस्थापन खानपुर जागीर की जब्ती के बाद, खानपुर परिवार को रातोंरात विस्थापित कर दिया गया। उन्होंने फिर से बासी बंगा गांव में बसने का फैसला किया, जिसे उनके पूर्वज शेख रुकनुद्दीन खान ने गंगा नदी के किनारे स्थापित किया था। हाजी मुनीर खान के पोते, जनाब सईद-उर-रहमान, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और उन्हें बुलंदशहर जेल में कैद किया गया । वह अपने गांव बसी बांगर के पहले प्रधान चने गए और बाद में वह अपनी प्रधानी शराफत हुसैन को देकर चले गए। उसके बाद उनके पुत्र, सऊद-उर-रहमान, ने भारतीय सेना में शामिल होकर 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लिया।बारा बस्ती (Bara Basti) का नाम सुनते ही इतिहास के पन्नों में झांकने की इच्छा जागृत हो जाती है। बारा बस्ती का अर्थ “बारह बस्तियाँ” होता है, जो आज के बुलंदशहर, गाजियाबाद, और अमरोहा जिलों में स्थित हैं। इन गांवों का इतिहास मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल तक जाता है। इस इतिहास की शुरुआत होती है बासी बागर नामक गांव से, जिसे दाउदज़ाई अफगान सरदार के पुत्र शेख रुकनुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे स्थापित किया था। यह गाँव एक छोटे से ठिकाने से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना।शेख रुकनुद्दीन की वीरता के कारण उन्हें मुगल शासकों द्वारा सम्मानित किया गया, और उन्हें मानसबदार की पदवी प्राप्त हुई।

1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सेना ने खानपुर जागीर को जब्त कर लिया और इसे और इसके बाद उनके सहयोगी रहे सैयद मीर खान बहादुर को खानपुर जागीर एवं किला बतौर इनाम दिया गया और उनके चाचा जान फिशा खान को सरदाना की जागीर मिली । इस परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था जिसके चलते अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि , पेंशन और जगीरो के इनाम दिए।

खानपुर जागीर की जब्ती और खानपुर परिवार का विस्थापन खानपुर जागीर की जब्ती के बाद, खानपुर परिवार को रातोंरात विस्थापित कर दिया गया। उन्होंने फिर से बासी बंगा गांव में बसने का फैसला किया, जिसे उनके पूर्वज शेख रुकनुद्दीन खान ने गंगा नदी के किनारे स्थापित किया था। हाजी मुनीर खान के पोते, जनाब सईद-उर-रहमान, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और उन्हें बुलंदशहर जेल में कैद किया गया । वह अपने गांव बसी बांगर के पहले प्रधान चने गए और बाद में वह अपनी प्रधानी शराफत हुसैन को देकर चले गए। उसके बाद उनके पुत्र, सऊद-उर-रहमान, ने भारतीय सेना में शामिल होकर 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लिया।

WEB Cadence INDIA

SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY

Our Best Service

- Lead Manegment
- Help desk Manegment
- QR Code Generation
- School Manegment
- Inventory Manegment

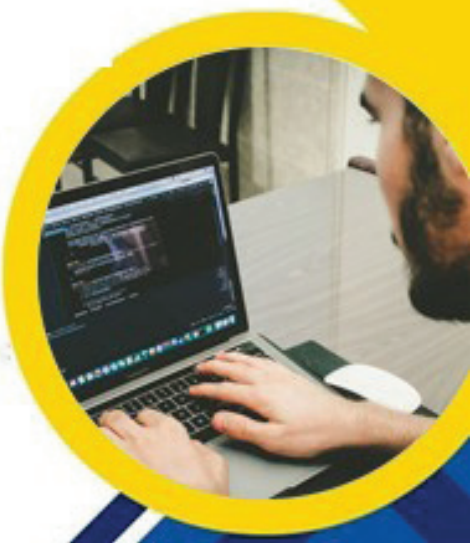

+91 7982133887 www.webcadenceindia.com asha@webcadenceindia.com

---

Mailing Solution
A Unit of Webcadence

Email Marketing

- Domain
- Bulk SMS/ Bulk Email
- Bulk Whatsapp
- Coporate Email

+91-98715-55245 admin@webcadenceindia.com www.mailingsolutions.in

बांग्लादेश के युध्द में आंखों के सामने साथियों को शहीद होते देखा, फिर यादें हुई ताजा

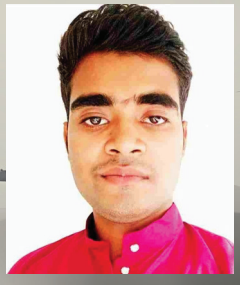

अरुण मौर्य
नोएडा

- शेख मुजीब-उर-रहमान के परिवार को धनमंडी स्थित एक घर में पाकिस्तानी सेना ने बंधक बनाया
- बिना किसी हथियार के कर्नल अशोक कुमार तारा ने पाकिस्तानी कमांडर सहित 12 सैनिकों से आत्मसमर्पण कराया
- ऑपरेशन बेटल ऑफ गंगासागर के जरिए कर्नल ने ढ़ाका एयरपोर्ट पर किया कब्जा
- बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर सेवानिवृत्ति कर्नल ने चिंता जाहिर किया

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को हुए तख्तापलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आने पर एक बार फिर से 1971 के युद्ध की यादें ताजा हो गई हैं। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा बंधक बनाए गए शेख हसीना के परिवार की जान बचाने वाले नोएडा सेक्टर-28 निवासी सेवानिवृत्त कर्नल अशोक कुमार तारा ने तख्तापलट होने के बाद अपनी पुराने यादें को साझा करते हुए चिंता जाहिर किया। साथ ही सरकार से शेख हसीना को देश में सुरक्षित रखने और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के लिए नियमित प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हुई घटना हमारे देश के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं हैं। इस घटना को देखने बाद उनके आंखों के सामने बांग्लादेश की वह लड़ाई फिर से ताजा हो गई है। जिसमें उन्होंने अपने कई साथियों को आंखों के सामने शहीद होते देखा। हिन्दुस्तान के साथ उस दौरान की यादों को साझा करते हुए सेवानिवृत्त कर्नल अशोक कुमार तारा ने बताया कि वह 1971 युद्ध के दौरान मिजोरम चिटगांव में 14 वीं गार्ड बटालियन में मेजर के पद पर तैनात थे। वह बांग्लादेश की तरफ से आ रहे भारी संख्या में शरणार्थियों की देखरेख और बांग्लादेश मुक्त वाहिनी के स्वंय सेवकों की मदद करने में लगे थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की स्वातंत्रता के कई ऑपरेशन में मुक्तवाहिनी के स्वंयसेवकों के साथ भाग लिया। कर्नल ने बताया कि बेटल ऑफ गंगासागर ऑपरेशन के जरिए उन्होंने अपनी टीम के साथ ढ़ाका एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। तब तक पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी दौरान मुक्तवाहिनी के एक स्वंयसेवक से सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब-उर-रहमान के परिवार को धनमंडी स्थित एक घर में बंधक बना लिया है। जो कि शेख मुजीब-उर-रहमान के पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे। सीनियर ऑफिसर ने इस दौरान उनको शेख के परिवार को सुरक्षित बचाने की जिम्मेदारी दी।

जीप पर दो जवानों के साथ वह निकल पड़े

कर्नल तारा ने बताया कि युध्द के दौरान सीनियर ऑफिसर के तरफ से आदेश मिलते ही वह अपने दो जवानों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए। धनमंडी स्थित जिस घर में शेख मुजीब-उर-रहमान के परिवार को बंधक बनाया गया था। उसके सामने जा पहुंचे। वहां पर चारों तरफ तबाही और कोहराम मचा हुआ था। कई लाशें सड़क पर पड़ी थी। पास के घर और कारों में आग लगी हुई थी। घर के पास पाकिस्तानी सेना ने चार बंकर तैयार करके रखा था। वह अपना हथियार और दोनों जवानों को जीप के पास छोड़ कर आगे बढ़ने लगे और पाकिस्तानी सैनिकों को घर- परिवार की याद दिलाते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहने लगे। पाकिस्तानी जवानों को बताया की उनकी सेना समर्पण कर चुकी है, लेकिन उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सीनियर सैन्य अधिकारियों से बात करने की बात कही। इसके साथ ही कर्नल को जान से मारने की धमकी देते हुए वापस लौट जाने के लिए बोलने लगे।

उड़ते हेलीकॉप्टर देख कमांडर की आवाज हुई धीमी

कर्नल तारा ने बताया कि 17 दिसंबर 1971 की दोपहर के समय वह करीब 30 मिनट तक पाकिस्तानी सैनिक से उनके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचाने की बात कहकर सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक फायरिंग हुई। जिसकी गोली उनकी सिर के ऊपर से निकल गई। पाकिस्तानी जवान हथियार से लैस थे। ऐसे में उनको घबराहट भी हो रही थी। लेकिन पीछे नहीं हटे थे। मौके पर डटे रहे। तभी सेना का एक हेलीकॉप्टर घर के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। इस दौरान कमांडर की आवाज थोड़ी सी धीमी पड़ गई। उन्होंने पाकिस्तानी जवानों से वादा किया कि अगर वह समर्पण कर देते हैं तो उन्हें मुख्यालय तक पहुंचा देंगे। जहां से वो अपने घर जा सकेंगे। तब उनको भी समझ आ गया था। पाक कमांडर के साथ 12 जवान थे। सभी ने समर्पण कर दिया। इस कार्य के लिए सरकार ने कर्नल तारा को वीर चक्र से सम्मानित किया।

शेख हसीना की मां दरवाजा खुलते ही उनसे लिपट गई

कर्नल तारा ने बताया कि जब वह पाकिस्तानी सैनिकों से आत्म समर्पण करा लिए। तो तुरंत उनको जीप से वहां से भेज दिया और घर के अंदर का दरवाजा खोला। इस दौरान शेख हसीना की मां दौड़ते हुए आई और उनसे लिपट कर बोली कि खुदा ने उनके लिए बेटा भेजा है। जिसने उनके परिवार को जुल्मियों से बचा लिया। इस दौरान उन्होंने शेख हसीना,उनकी बहन रिहाना, रशद और चार महीने के उनके छोटे बेटे जोय को सुरक्षित बचा लिए। शेख हसीना के पिता शेख मुजीब-उर-रहमान के चचेरे भाई ने उन्हें बांग्लादेश का झंडा दिया और उन्होंने उस झंडे को छत पर लहरा कर पाकिस्तान के झंडे उखाड़ कर फेंक दिया। शेख परिवार आज भी उनका अहसान मानता है। उनके साथ परिवार के अभी तक रिश्ते बने हुए हैं, जिसके बाद कई मौके पर उनको घर बुलाया गया। यही कारण है कि उन्हें 2012 में बांग्लादेश के सर्वोच्च पुरस्कार फ्रेंड्स आफ लिबरेशन वार आनर्स दिया गया। वहीं 2017 भारत दौरे के दौरान शेख हसीना ने कर्नल अशोक कुमार तारा और उनकी पत्नी आभा तारा से भेंट भी की।

देश के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं

बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर कर्नल अशोक कुमार तारा ने कुछ देशों की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रविवार को शेख हसीना ने देश छोड़ा और उसके बाद सैन्य प्रमुख ने तख्तापलट की घोषणा की यह सिर्फ आंतरिक विरोध प्रदर्शन नहीं है। एक पड़ोशी देश के तौर पर बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं। वह भारत के लिए ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सीमा से जुड़े राज्यों में सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही फिर से शरणार्थी समस्या भी देश के सामने होगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा को लगेंगे चार चांद, जेवर एयरपोर्ट की तैयारी में झोंकी जान !

सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की सहूलियत के लिए कई ख्वाब देखे है. साथ ही इन सपनों को पंख देने का काम भी जी जान से किया है. सीएम योगी के इन्हीं सपनों में से एक है ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये एयरपोर्ट सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है और जल्द ही ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान भरने को भी तैयार हो जाएगा. नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अप्रैल 2025 में पहली उड़ान की शुरुआत की जायेगी. जिसको लेकर तैयारियां अपनी चरम सीमा पर हैं. वहीं दिसंबर 2024 तक पहले फेस का काम पूरा हो जाएगा. बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनकर तैयार हो रहा है.

बनारस के घाट की तर्ज पर तैयार हो रहा फॉरकोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बन रहे टर्मिनल का काम भी काफी तेजी से चल रहा है.1 लाख स्क्वायर मीटर में बनाए जा रहे टर्मिनल में आधुनिकता के साथ-साथ यूपी के विरासत की भी झलक देखने को मिलेगी. टर्मिनल के फॉरकोर्ट को बनारस के घाट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. नोएडा एयरपोर्ट से सितंबर 2024 में पैसेंजर फ्लाइट की उड़ान का संचालन शुरू होना था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया. अब अप्रैल 2025 से पैसेंजर फ्लाइट के संचालन शुरू होने की संभावना है. नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण में 12 मिलियन पैसेंजर की क्षमता होगी. टर्मिनल में फ्लाइट्स फ्यूलिंग सर्विसेज, ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सहित प्रमुख एयर कंडीशनर का काम पूरा हो गया है.

3.9 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान के लिए 3.9 किलोमीटर और

चौड़ाई 60 मीटर का रनवे बनकर तैयार हो चुका है. इसके साथ ही एयरपोर्ट की टर्मिनल की बिल्डिंग का ढांचा भी बनाकर तैयार हो गया है. इसमें 10 गेट बनाए जा रहे हैं और यहां पर बन रहे एटीसी टावर का काम भी लगभग लगभग पूरा हो गया. वहीं रनवे पर एस्फाल्ट एवं डामर का काम भी पूरा हो गया है. रनवे मार्किंग, एप्रोच लाइट और एयर फील्ड ग्राउंड लाइटिंग पर काम जारी है. इसके अलावा यहां का ड्रेनेज सिस्टम खास तकनीक से बनाया गया है. ताकि बारिश में वाटरलॉगिंग न हो पाए.

दिसंबर 2024 में होगी फ्लाइट की ट्रायल और टेस्टिंग

ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यूपी सरकार के साथ 40 साल के लिए समझौता हुआ है. यह करार 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था. एयरपोर्ट के पहले चरण का काम लगभग 1,334 हेक्टेयर में फैला हुआ है. इसका निर्माण चार चरणों में किया जाना है. इसका पहला चरण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और पहले चरण के दौरान एक रनवे और एक टर्मिनल भी तैयार हो रहा है. जो हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार होगा. टर्मिनल और बाकी कामों को पूरा कर लिया गया है. एयरपोर्ट उपकरणों की जांच के लिए सितंबर व अक्टूबर में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच होगी. दिसंबर में वैलिडेशन और टेस्ट फ्लाइट के बाद एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा. इसके साथ ही दिसंबर 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट की ट्रायल और टेस्टिंग की जानी शुरू कर दी जाएगी और अप्रैल 2025 से यहां पर उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी.

पूरी तरह से डिजिटल होगा नोएडा एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. इसमें इनडोर, नेविगेशन, पैसेंजर, फ्लोर, मैनेजमेंट, स्मार्टफोन द्वारा चेक इन, बैगेज, ड्रॉप और सभी चेकप्वाइंट पर डिजिटल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.

CISF जवानों के हाथों में होगी सुरक्षा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथ में होगी. सीआईएसएफ के 1047 जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे. जो 24 घंटे एयरपोर्ट की निगरानी करेंगे. गृह मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है. सुरक्षा बल के जवानों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था एयरपोर्ट की संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगी. इसके साथ ही सीआईएसएफ के अविवाहित जवानों के लिए एयरपोर्ट परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा. जबकि विवाहित जवानों को आवासीय सुविधा के लिए परिसर से बाहर इंतजाम किए जाएंगे.

साल 2021 में PM मोदी ने रखी थी आधारशिला

नोएडा का जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस एयरपोर्ट पर छह रनवे होंगे. जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से दोगुने होंगे. साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी. इस एयरपोर्ट को तैयार करने में अनुमानित लागत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये है. नोएडा एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. जो यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस एयरपोर्ट के बन जाने से गौतम बुद्ध नगर सहित एनसीआर, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा. इस एयरपोर्ट से यातायात कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए आसपास के कई राज्यों से हाईवे को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा

THE PLEASURE OF
VARIETY ON YOUR PLATE
COUNT THE MEMORIES NOT
THE CALORIES
More Information
9910625795
More Information
www.thestreetviewrestro.com

What Are You
Craving For ?
KURKURE MOMOS
NOODLES
FRENCH FRIES
FRIED RICE
More information
9910625795
More information
www.thestreetviewrestro.com

ग्रेटर नोएडा में पहला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट

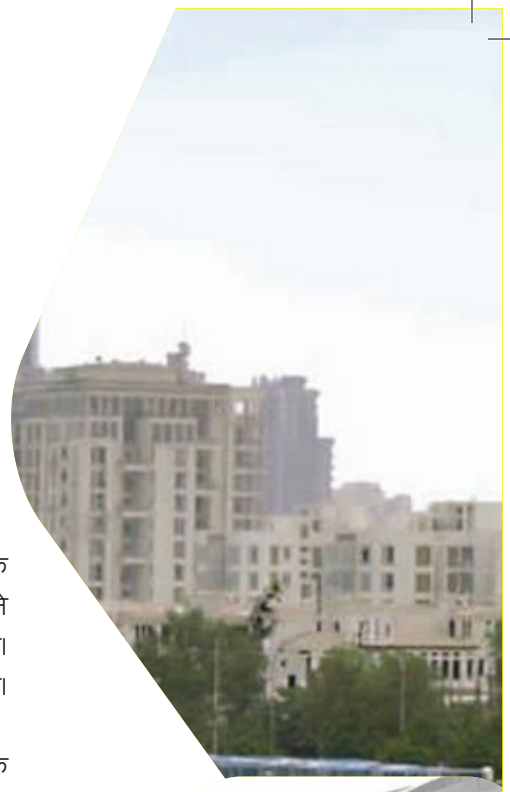

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच 9 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच का दर्शक निःशुल्क लुत्फ़ उठा सकेंगे। मैच देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान बोर्ड ने यह फैसला लिया है। स्टेडियम में दर्शकों का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। मैच के दौरान दर्शकों को सुबह 8 बजे से प्रवेश मिलेगा।

शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नौ से 13 सितंबर तक न्यूजीलैंड व अफगानिस्तान के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच का दर्शक निश्शुल्क लुफ्त उठा सकेंगे। निश्शुल्क मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर टिकट काउंटर खोले जाएंगे। स्टेडियम के बाहर भी कई काउंटर होंगे। जहां दर्शक पहुंचकर भी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वेबसाइट और जगह का चयन किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में वेबसाइट और काउंटर की जानकारी दे दी जाएगी। अगले सप्ताह से दर्शक मैच देखने के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सुरक्षा को देखते हुए अफगानिस्तान बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया है।

स्टेडियम में पहुंचने वाले हर क्रिकेट प्रेमियों का डाटा सुरक्षित रखा जाएगा और यह जानकारी में मिल सकेगी कि पांच दिन तक कितने क्रिकेट प्रेमियों ने मैच का रोमांच उठाया। इसके साथ ही कहां कहां से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच देखने के लिए दर्शक पहुंचे है। निश्कुल प्रवेश होने के कारण अफगानिस्तान बोर्ड, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाती कि प्रतिदिन कितने दर्शक मैच देखने के लिए पहुंच रहे है। दर्शकों की जानकारी होने पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा।

स्टेडियम में दर्शकों को सुबह आठ बजे से प्रवेश मिलने लगेगा। दोनों देशों की टीम सुबह नौ बजे तक स्टेडियम में पहुंच जाएगी। पहले अफगानिस्तान और उसके 20 मिनट बाद न्यूजीलैंड की टीम पहुंचेगी। सुबह साढ़े नौ बजे टॉस होगा। सुबह 10 से पांच बजे तक मैच होगा।

टीम के आने के दौरान दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। वीवीआइपी और खिलाड़ी का प्रवेश एक ही गेट से होगा। स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए दर्शकों को रजिस्ट्रेशन के समय मिले कोड को दिखाना होगा। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच के सफल आयोजन के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में स्टेडियम में 12 हजार दर्शक क्षमता है। दर्शक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेडियम में दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में स्टेडियम में 25 हजार दर्शक मैच का लुफ्त उठा पाएंगे। दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां आईपीएल मैच मिलने की संभावनाएं भी अधिक होगी।

UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
Transaction
Successful

अब बिना अकाउंट कर सकेंगे एक साथ 5 लोग UPI Payment !

कई बार ऐसा होता है न, जब मम्मी-पापा या दोस्तों के साथ कहीं जाते है तो जेब में खुल्ले पैसे नहीं होते तो पहला सवाल दुकानदार से यही होता है की भइया क्या UPI कर दें, ये एक ऐसा चलन है जिसने जेब में पैसे रखने की आदत को ही भूला दिया है क्योंकि आजतक करोड़पति से लेकर सड़क पर सब्जी बेचने वाला भी UPI ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करता है. अब लोग कैश ले जाने के बजाय अपना मोबाइल फोन लेकर जाते हैं और मार्केट से पूरी खरीदारी कर लेते हैं. भारत में गली-गली या ये कह लें की अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 2 से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का USE करते हैं, हालांकि अब RBI ने एक ऐसा सिस्टम ला दिया है जिसके बाद घर का एक, दो नहीं बल्कि पांच के पांचों लोग UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे.

UPI में एक साथ जुड़ेंगे 5 लोग !

दरअसल UPI का ट्रेंड भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है. बीते चंद महीने की ही बात करें तो अप्रैल से जुलाई के बीच 81 लाख करोड़ से ज्यादा का लेनदेन हुआ है. UPI को 2016 में लॉन्च किया गया. इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बनाया है. इसने आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी. इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था. वॉलेट में KYC जैसी झंझट है, जबकि UPI में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. हालांकि अब तो एक UPI से 5 लोग जुड़ सकते है, इतना ही नहीं अगर बैंक अकाउंट नहीं है तब भी UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं.

RBI ने लॉन्च किया UPI Circle

रिपोर्ट्स की मानें तो RBI ने अब UPI यूजर्स के लिए UPI Circle फीचर को लॉन्च कर लिया है. इस नए फीचर के आने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो शेयरिंग इज केयरिंग पर भरोसा करते हैं. देखा जाए तो आज भी घर में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनमें परिवार के मुखिया के पास बैंक अकाउंट है लेकिन घर में बुजुर्गों, बच्चों और घर में रहने वाली महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं है. ऐसे में ये सभी लोग पेमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं. इसीलिए UPI Circle फीचर ऐसे ही लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है. बताया जा रहा है ये सर्कल फीचर उन लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए कैश पेमेंट करते है.

तय हुई ये लिमिट !

आसान भाषा में कहें तो UPI सर्कल एक ऐसा फीचर है जो एक प्राइमरी यूज़र को इस बात की इजाजत देता है कि वो एक सेकेंडरी यूज़र को UPI ट्रांज़ैक्शन करने का अधिकार दे सकें. इसमें ट्रांज़ैक्शन की सीमा को सेट किया जा सकता है. प्राइमरी यूजर का मतलब है UPI का वो यूजर, जो किसी और यूजर यानी सेकेंडरी यूजर को अपने बदले में UPI पेमेंट करने के लिए Authority देता है. ये अधिकार दो तरह का हो सकता है – फुल और पार्शियल डेलिगे

Full Delegation का मतलब यह है कि सेकेंडरी यूजर को एक लिमिट तक हर पेमेंट के लिए प्राइमरी अकाउंट होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं होगी. फुल डेलिगेशन के तहत, हर ट्रांज़ैक्शन की लिमिट 5000 रुपये और एक महीने में अधिकतम लेन-देन की लिमिट 15,000 तक हो सकती है.

Partial Delegation में सेकेंड्री यूजर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज पाएगा. ये पेमेंट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक प्राइमरी अकाउंट होल्डर पेमेंट को अप्रूव नहीं कर देता है. वहीं ट्रांजैक्शन के लिए UPI PIN की जरूरत पड़ती है. बता दें इसी डेलीगेशन के तहत एक प्राइमरी यूज़र 5 सेकेंडरी यूज़र्स को डेलिगेट कर सकता है, जबकि सेकेंडरी यूज़र केवल एक ही

प्राइमरी यूज़र की तरफ से डेलिगेशन का अधिकार स्वीकार कर सकता है. आंशिक डेलिगेशन के मामले में UPI की मौजूदा लिमिट ही जारी रहेगी.

बुजुर्गों से लेकर बच्चों को सहलूयित

एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि UPI सर्कल उन यूजर्स को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मुहैया कराता है, जो अब तक ऐसा करने से हिचकते रहे हैं. ऐसे पेरेंट्स जिन्हें अपने कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे को पैसे भेजने हैं, या उसके किसी खर्च के लिए पेमेंट करना है, ऐसे बुजुर्ग जो डिजिटल पेमेंट्स करने में दिक्कत महसूस करते या घबराते हैं, ऐसे बिजी लोग, जो अपने रोज-रोज के घरेलू खर्चों के लिए होने वाले पेमेंट्स का काम किसी और को सौंपना चाहते हैं, या ऐसे बिजनेसमैन जो अपने स्टाफ को छोटे-मोटे खर्चों के लिए नकद पेमेंट करने की बजाय डिजिटल तरीके से भुगतान करना चाहते हैं. ये सभी लोग, अब UPI सर्कल के जरिये सेकेंडरी यूजर को डेलिगेट करके आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे. फुल और पार्शियल डेलिगेशन की सुविधा के कारण वो ये भी तय कर पाएंगे कि किस सेकेंडरी यूजर को उन्हें पेमेंट के मामले में कितना अधिकार देना है और कितना नहीं. NPCI के इस नए प्रोडक्ट को देश में डिजिटल पेमेंट के विस्तार में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

UPI से हर सेकेंड 3 हजार से ज्यादा लेनदेन

हाल ही में ग्लोबल पेमेंट्स हब पेसिक्योर की ओर से जारी किए गए लेटेस्ट डेटा में कहा गया है कि UPI से हर सेकेंड 3,729 लेनदेन हो रहे हैं. 2022 में ये आंकड़ा 2,348 लेनदेन प्रति सेकेंड था. इस दौरान UPI से लेनदेन में 58 फीसदी का इजाफा देखा गया है. आंकड़ों के मुताबिक UPI लेनदेन की संख्या के मामले में भारत, चीन के अलीपे, अमेरिका के पेपाल और ब्राजील के पिक्स से काफी आगे निकल गया है. जुलाई में UPI से कुल 20.6 लाख करोड़ रुपए के लेनदेन हुए. ये अब तक दर्ज किया गया UPI लेनदेन का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसके अलावा UPI से होने वाले लेनदेन की कुल वैल्यु लगातार 3 महीने से 20 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बनी हुई है. पेसिक्योर के डेटा के मुताबिक, दुनिया में डिजिटल लेनदेन के मामले में भारत टॉप पर है. यहां 40 फीसदी के करीब लेनदेन डिजिटल तौर पर किए जाते हैं. डिजिटल भुगतान करने के लिए लोग सबसे ज्यादा UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

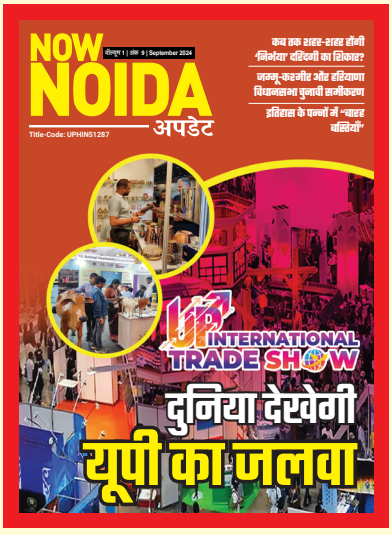

पत्रिका सदस्यता प्रपत्र

भारत के व्यक्तियों के लिए वार्षिक सदस्यता: ₹ 440 ☐

भारत के बाहर और कॉर्पोरेट दरें: ₹ 2,000 ☐

Name .....

Address.....

.....

.....

.....

Postcode.....

Telephone.....

Email.....

कृपया चेक या पोस्टल ऑर्डर करें

MBI Digital Private Limited को देय।

MBI
Direct From Factory

FASHION COLLECTION

SPECIAL OFFER

USE COUPON CODE:

FLAT20

UPTO
20%
OFF

SHOP NOW

sales@madebyindia.com

+91 07011412854